www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन से भेंट

वर्ष-14, अंक-18 16-30 सितम्बर, 2019 (पाक्षिक) ₹20

मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन

- जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए निरस्त
- भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु बैंकों का विलय, टैक्स दरों में कमी और अन्य कदम उठाए गए
- तीन तलाक के खिलाफ कानून, मुस्लिम महिलाओं को मिली इस कुप्रथा से मुक्ति
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) क़ानून (यूएपीए) में संशोधन कर राष्ट्रीय सुरक्षा में और मजबूती
- 1,25,000 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, PMGSY III का शुभारंभ
- नौकरशाही में फैले भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई
  15 कस्टम व एक्साइज तथा 34 कर अधिकारी भ्रष्टाचार मामलों के कारण हटाए गए

अरुण जेटली

(28 दिसम्बर, 1952 – 24 अगस्त, 2019)

शत शत नमन!

श्री अरुण जेटली के निधन के बाद नई दिल्ली में उनके आवास पर परिवारजनों को सांत्वना देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में संपन्न एक श्रद्धांजलि सभा में श्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में संपन्न एक श्रद्धांजलि सभा में श्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

श्री अरुण जेटली की अंतिम यात्रा

नई दिल्ली स्थित निगम बोध घाट पर पंचतत्व में विलीन होता श्री अरुण जेटली का पार्थिव शरीर

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 देश में विकास, पहल और बड़े बदलाव के प्रथम 100 दिन

केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर 8 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री जावडेकर ने पुस्तिका 'जन कनेक्ट' का विमोचन किया और 'भारत के विकास को प्रोत्साहन-100 दिनों की साहसिक...

वैचारिकी

भारतीय जीवन पद्धति आज भी मार्गदर्शन कर सकती है 15

श्रद्धांजलि

नहीं रहे अरुण जेटली 18

लेख

सियासी सफर के साथी का जाना 23
वैचारिक राजनीति के अग्रदूत 24
मोदी सरकार के ऐतिहासिक प्रथम 100 दिन 26

अन्य

भाजपा के बने 7 करोड़ नये सदस्य 10
10 बैंकों के विलय से बनेंगे चार बड़े बैंक 14
जो फिट है, वह हिट है और बाडी फिट तो माइंड हिटः नरेंद्र मोदी 17
'पूरे देश में नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया' 22
प्रधानमंत्री की फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की सफल यात्रा 28
भारत-रूस के बीच हुए 15 समझौते 31
केंद्रीय गृह मंत्री ने दादरा नगर हवेली के सिलवासा में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ किया 32
हमारी लड़ाई आतंकियों से है और आपकी भीः अमित शाह 33
एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ जन-आंदोलन का आह्वान 34

09 भाजपा से जुड़े रहना भाग्य की बातः जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 अगस्त को लोहरदगा में कहा...

11 जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा से भेंट

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के व्यापक...

12 कोयला खनन और ठेका विनिर्माण में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की...

13 वायुसेना में शामिल हुए आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर

अमेरिका निर्मित आठ 'अपाचे एएच-64ई' लड़ाकू हेलीकॉप्टर तीन सितम्बर को भारतीय वायुसेना में...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, उसके काम में सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के हित को दी जाती है। हम टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं सोचते, बल्कि एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं।

@AmitShah

चाहे जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाना हो या मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्त करना या UAPA कानून को मजबूत कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह सभी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता व राष्ट्रहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं।

@JPNadda

जीवन जीने एवं व्यवसाय करने में सरलता प्रदान करने हेतु पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने 1400 से अधिक पुराने एवं व्यर्थ कानूनों को निरस्त किया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मोदी 2.0 ने 100 दिनों में 58 पुराने एवं व्यर्थ कानूनों को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

facebook

कांग्रेस तो अपने पापों के कारण समाप्त हो रही है। जैसे भ्रष्टाचार के आरोप इनके समर्थक, मंत्री और नेता लगा रहे हैं, वैसे आरोप किसी और सरकार में कभी नहीं लगे थे। मुझे तो चिंता केवल मध्यप्रदेश की है, जिसको ये तबाह और बर्बाद किये जा रहे हैं।

— शिवराज सिंह चौहान

राशन कार्ड धारक प्रदेश के हर परिवार को महीने में 2 किलो दाल बाजार भाव से बहुत कम दरों पर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत की गई है। नजदीकी सरकारी राशन की दुकान में जाकर इस योजना का लाभ उठाएं।

— त्रिवेन्द्र सिंह रावत

महर्षि अरविंद ने कहा था कि सबसे बड़ा धर्म है "राष्ट्र धर्म"। राष्ट्र धर्म ही है जो हमें महसूस कराता है कि कश्मीर में धारा 370 विकास को रुद्ध करती है, देश को विभाजित करती है, वहां के नागरिकों के अधिकारों को रौंदती है, इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए था।

— योगी आदित्यनाथ

अरुण जेटली

(28 दिसम्बर, 1952 – 24 अगस्त, 2019)

शत शत नमन!

कमल संदेश

परिवार की ओर से

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली

को विनम्र श्रद्धांजलि!

देश में व्यापक परिवर्तन का युग शुरू

मोदी सरकार ने अपनी दूसरी पारी के सौ दिन पूरे कर लिए। इन सौ दिनों में अनगिनत उपलब्धियों का अंबार लगाते हुए करोड़ों जनों के स्वप्न साकार हुए हैं। कुछ उपलब्धियां तो इतनी अद्भुत हैं कि उनसे भारतीय राजनीति की दिशा बदल गई है और पूरा देश नए आत्मविश्वास एवं उत्साह से सराबोर है। धारा 370 एवं 35ए की समाप्ति तथा जम्मू–कश्मीर राज्य का पुनर्गठन ऐसी उपलब्धि है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित हो चुका है। यह एक ऐसा कदम है जिससे यह पता चलता है कि एक साहसी नेतृत्व किस प्रकार से दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा अपने निर्णय पर कायम रहकर एक नया युग प्रारंभ कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विषय पर संसद के दोनों सदनों में जिस प्रकार का समर्थन विभिन्न राजनैतिक दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिया, उससे धारा 370 एवं 35ए की समाप्ति के पक्ष में देश की आम जनभावना परिलक्षित हुई है। यह भावना संसद में तब देखी गई जब तीन तलाक जैसी महिला विरोधी सामाजिक कुरीति पर विधेयक पारित हुआ। इससे देश में तुष्टीकरण की राजनीति के फलस्वरूप चल रही इस कुप्रथा की समाप्ति पर संसद की निर्णायक मुहर लग गई है। इसके अलावा अनेक पहलें, प्रमुख रूप से यूएपीए कानून में संशोधन तथा एनआईए को मजबूत किये जाने से आतंकवाद के विरुद्ध देश की लड़ाई को और भी अधिक बल मिला है। इन निर्णयों का दूरगामी परिणाम निकलेगा और यह स्पष्ट संदेश गया है कि देश आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश के इतिहास में सर्वाधिक सफल संसदीय सत्रों में से एक, यह पिछला सत्र रहा है जो देश की बदलती हुई कार्य-संस्कृति एवं जन-जन के विकास के लिये राजनैतिक प्रतिबद्धता का द्योतक है।

पिछले 100 दिनों में देश 'स्पीड, स्केल एवं स्किल' के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ा है और भाजपा करोड़ों लोगों के स्वप्न साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र एक नए उत्साह एवं आशा के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार की अभिनव योजनाओं से जहां एक ओर लोगों की आकाक्षाएं और अधिक पल्लवित हो रही हैं वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं का तीव्र कार्यान्वयन लोगों की अपेक्षाओं से भी अधिक हो रहा है। जैसे ही मोदी सरकार केन्द्र में पुनः जनादेश प्राप्त कर आई इसने देश में व्यापक आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आने वाले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश का निर्णय लिया है, जिससे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं तथा विभिन्न बैंकों के विलय से इस दिशा में आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा 'एनपीए' की समस्या पर भी सकारात्मक कदम उठाये गए हैं। सरकार ने अपने सभी प्रतिबद्धताओं पर त्वरित कार्रवाई की है। किसानों के लिए 'किसान सम्मान निधि' का दायरा बढ़ाकर 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ पहुंचाया है। खुदरा व्यवसायी एवं छोटे दुकानदारों के लिए पहली बार पेंशन योजना लाकर इस क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। जलशक्ति मंत्रालय की शुरुआत कर अब हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के लिए अनेक अभिनव योजनाएं क्रियान्वित कर पूरे देश में व्यापक परिवर्तन का युग शुरू हो चुका है।

जहां मोदी सरकार ने पिछले 100 दिनों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वहीं दूसरी ओर एक राजनैतिक संगठन के रूप में भाजपा ने 50 प्रतिशत से भी अधिक और नए सदस्यों को दल से जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल है। अब इसकी सदस्य संख्या 11 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ से भी अधिक हो गई है तथा पूरे देश में इसका आधार व्यापक एवं गहरा हुआ है। इस सर्वस्पर्शी एवं सर्व-समावेशी सदस्यता अभियान की जबरदस्त सफलता भाजपा की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हर लक्ष्य को समय से पूर्ण एवं अपेक्षा से अधिक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 'मां भारती' की सेवा में समर्पित भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं कार्यक्षमता वास्तव में अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाजपा का उदय आशा की एक नई किरण के रूप में हुआ है। पिछले 100 दिनों में देश 'स्पीड, स्केल एवं स्किल' के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ा है और भाजपा करोड़ों लोगों के स्वप्न साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन

देश में विकास, पहल और बड़े बदलाव के प्रथम 100 दिन

केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर 8 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री जावडेकर ने पुस्तिका 'जन कनेक्ट' का विमोचन किया और 'भारत के विकास को प्रोत्साहन-100 दिनों की साहसिक पहल और निर्णायक कार्रवाई' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व स्तर पर कई ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने इसरो के समर्पित वैज्ञानिकों के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संवेदनशीलता और प्रोत्साहन की और व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय को बढ़ावा देने की सराहना की।

श्री जावडेकर ने सरकार के प्रमुख निर्णयों का उल्लेख किया जिनमें- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को प्राप्त करने की दिशा में उठाये गए कदम, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश, व्यवसाय करने की सरलता, तीन तलाक के खिलाफ कानून, जीएसटी और आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में भौतिक हस्तक्षेप में कमी और पारदर्शिता, जल शक्ति अभियान, हर घर बिजली योजना, गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र संरक्षण, दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ी योजना- किसानों को वित्तीय सहायता, जनभागीदारी आन्दोलन, फिट इंडिया और एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे को खत्म करने के लिए अभियान, सुशासन का उपाय, संसद का उत्पादक सत्र, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इत्यादि शामिल हैं।

जीडीपी विकास दर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री जावडेकर ने जोर देकर कहा कि हालांकि अर्थव्यवस्था की मंदी चक्रीय है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं और विदेशी निवेश तथा घरेलू मांग में वृद्धि के साथ जीडीपी विकास दर में जल्द ही बढ़ोतरी होगी।

इन सौ दिनों में रिकॉर्ड काम हुए हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि केंद्र में उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे हुए हैं। इन सौ दिनों में रिकॉर्ड काम हुए हैं। संसद के बीते सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना पिछले साठ सालों में नहीं हुआ। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 सितंबर को हरियाणा के रोहतक में आयोजित जनसभा में कही।

श्री मोदी ने कहा कि ये सौ दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं और देश में होने वाले परिवर्तन के रहे हैं। ये सौ दिन सरकार के निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं और नेकनीयत के रहे हैं। ये सौ दिन जनसंकल्प और जन सिद्धियों के रहे हैं और जन सरोकार के रहे हैं, जिसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन देश के 130 करोड़ भारतवासी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत हर चुनौती को चुनौती देता है। चाहे जल संकट हो या कोई और संकट, 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर समाधान खोजना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "बीते चार महीने में सरकार ने अपने कई और संकल्प पूरे किए हैं। मौजूदा सरकार ने देश के 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा कर लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने 2024 तक हर घर को जल पहुंचाने जैसा बड़ा संकल्प लिया है। इस योजना पर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।" प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए तीन हजार रुपये मासिक पेंशन की योजना भी शुरू हो चुकी है और इससे जहां देश में 8 लाख व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सात करोड़ और हरियाणा के 13 लाख किसानों को लाभ मिला है।

मोदी सरकार राष्ट्र सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण की पर्याय है : अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले गिनाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्र सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण की पर्याय है। ये सरकार देश के हर वर्ग की आशाओं की प्रतीक है।

श्री शाह ने कहा कि अपने द्वितीय कार्यकाल के 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसकी राह हर देशवासी 70 सालों से देख रहा था। चाहे जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए हटाना हो या मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्त करना या यूएपीए कानून को मजबूत कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो। यह सभी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता व राष्ट्रहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं।

श्री शाह ने कहा कि मैं समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी सरकार आपके विकास, कल्याण और सुरक्षा के लिए निरंतर कटिबद्ध है। बता दें लोकसभा चुनाव में दूसरी बार बहुमत हासिल कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने दूसरी बार सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मई को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

ट्रिपल तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई: थावर चंद गहलोत

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने 100 दिनों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए 9 सितंबर को कहा कि मंदी का वातावरण भयभीत करने वाला नहीं हैं। रायपुर में आयोजित पत्रकार-वार्ता में श्री गहलोत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। रोजगार निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बैंक से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है।

100 दिनों की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को मुख्यधारा में लाना, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और अतिरिक्त क्रेडिट विस्तार बैंक ऋण की ब्याज दरों में समय पर कटौती ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गति के उपाय, 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन को अंतिम रूप देने के लिए गठिक एक अंतर मंत्रालय इन कार्यबल के माध्यम से व्यापक आर्थिक सुधार किया जा रहा हैं। सीएसआर उल्लंघन को नागरिक दायित्व के रूप में माना जाएगा।

400 करोड़ रुपए से कम के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों के कारपोरेट कर में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया गया। पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया बच्चों के यौन हमले के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019-ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण और भेदभाव की रोकथाम जोकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को परिभाषित करता है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार 6.37 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य, रेल को देश का विकास इंजन बनाने के लिए 2030 तक निवेश 50 लाख करोड़ रुपए करने की योजना हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 150 एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है, 55 पहले से चालू है, 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को बिजली और गैस कनेक्शन सुनिश्चित करने का लक्ष्य, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया

जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 100 दिनों के भीतर 8 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया हैं।

80 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है, चंद्रयान-2 के माध्यम से नए क्षितिज की खोज की जा रही है। सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का निर्णय लिया गया, अपाचे-हेलीकॉप्टरों को हवाई बेड़े में शामिल किया गया। धारा 370 निरस्त करने के फैसले के साथ जी-7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे बड़े देश खड़े हैं। भारत का वैश्विक कद बढ़ा है। ग्लोबल लीडरशिप में भारत अग्रणी रहा हैं।

8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिला: रमेश पोखरियाल 'निशंक'

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर 9 सितंबर को देहरादून में एक प्रेस कांफ्रेंस की। हाल के महीनों में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्णायक कदमों की बहु-आयामी प्रकृति एक ऐतिहासिक घटना रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि लंबे समय से चले आ रहे आतंकी माहौल पर कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में यथास्थिति में बदलाव से इसे न सिर्फ भारत के साथ जोड़ा गया है, बल्कि इससे कश्मीर के लोगों को भी लाभ होगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लाभ के सीधे स्थानांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा से सात महीने पहले ही 8 करोड़ लाभार्थी परिवारों को गैस कनेक्शन देने का मुकाम हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतिबद्धता सरकार के हर काम को चित्रित करती है।

चंद्रयान-2 के लैंडर 'विक्रम' का जिक्र करते हुए पोखरियाल ने कहा कि इसने 3,84,000 किलोमीटर का सफर सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने सफर के आखिरी हिस्से में वह लड़खड़ा गया। अंतरिक्ष की यह यात्रा आगे के विकास की दिशा में एक कदम है।

उन्होंने इसरो के वैज्ञानिक समुदाय के प्रति माननीय प्रधानमंत्री के संवेदनशील भाव की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने देश में उच्च शिक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आईआईटी और राष्ट्रीय महत्व वाले दूसरे संस्थानों को विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों पर श्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि काफी समय से लंबित 2,675 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) फंड के तहत जारी कर दी गई है।

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर: अर्जुन मुंडा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर 9 सितंबर को रांची में केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 100 दिनों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करते हुए कई साहसिक फैसले लिए हैं। "एनडीए-2 ने 100 दिन के कालखंड में नया इतिहास बनाने का कार्य किया है। इसी तरह जनता को किए हुए वादों को अगले पांच सालों तक आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार पूरे देश के लिए कार्य कर रही है, जिससे सबका लाभ हो, सबके मौलिक हितों की रक्षा हो और उसे अपना हक मिले। हम देश के हितों को अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं," श्री मुंडा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा।

सरकार द्वारा कश्मीर से 370 और 35A हटाने, आर्थिक क्षेत्र में किए गए सुधारों, खासकर सरकारी बैंकों के एकीकरण और कारोबार में सुगमता से जुड़े हुए फैसलों से तात्कालिक समय के साथ दूरगामी स्थिति में जहां देश को फायदा पहुंचेगा, वहीं अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इस तरह हम अपने लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कश्मीर से 370 और 35A हटाने, आर्थिक क्षेत्र में किए गए सुधारों, खासकर सरकारी बैंकों के एकीकरण और कारोबार में सुगमता से जुड़े हुए फैसलों से तात्कालिक समय के साथ दूरगामी स्थिति में जहां देश को फायदा पहुंचेगा, वहीं अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इस तरह हम अपने लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर होंगे।

इन 100 दिनों में सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के जरिये जल क्षेत्र को बढ़ाने, बारिश के पानी को रोकने और भविष्य के लिए जल सुरक्षा जैसे महत्वाकांक्षी कार्य करने की योजना बनाई है।

वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कई अहम निर्णय लिए गए जिसमें तीन तलाक को दंडनीय जुर्म बनाना सबसे सराहनीय कार्य रहा। भ्रष्टाचार पर भी सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। देश की जनता को एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जरूरत है। इस दौरान भारत ने इनोवेशन इंडेक्स पर भी लंबी छलांग के साथ 52 स्थान प्राप्त किया, जो देश की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। ■

भाजपा से जुड़े रहना भाग्य की बात: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 अगस्त को लोहरदगा में कहा कि भाजपा से जुड़ना भाग्य की बात है। हम यह गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या आज इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि विश्व में अभी केवल सात ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भाजपा के सदस्यों की संख्या से अधिक है। हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या के कारण ही हम मजबूत हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ा हौसला किसी के पास नहीं है। किसी और दल के कार्यकर्ताओं में दम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर है। श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह ने देश को एक दिशा दी है। श्री अमित शाह ने कहा है कि अभी अच्छे दिन बाकी हैं, अभी बंगाल बाकी है। झारखंड के बाद अन्य विधानसभा चुनाव भी बाकी हैं।

लोहरदगा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि इस बार 65 पार नहीं, बल्कि हमें 80 पार सीटें लानी है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता जी जान में जुट जाएं। जनता भाजपा की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भाजपा ने जिस तरह से जनता के हित में विकास कार्य किए हैं, उसके बाद इस बार हम 80 पार सीटें लाएंगे। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं से कई बार 80 पार के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहरदगा लोकसभा चुनाव में सुदर्शन चक्र चला था। इस बार विधानसभा चुनाव में भी लोहरदगा से जीत का आह्वान करते हैं।

लोहरदगा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत प्लास्टिक मुक्त भारत बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है, हमें उसे मिलकर पूरा करना है। प्लास्टिक का उपयोग हमें पूरी तरह से बंद कर देना है। श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से जो वादा किया था, उसे 100 दिन से पहले पूरा कर के दिखाया है।

महाराष्ट्र

'राहुल गांधी बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 अगस्त को कहा कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। श्री नड्डा महाराष्ट्र के जालना में पार्टी के चुनाव से पहले संपर्क अभियान 'महा जनादेश यात्रा' को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद थे।

श्री नड्डा ने श्री राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर पर उनके बयान का पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ''राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।'' श्री नड्डा ने कहा, ''अब वह पीछे हट गए हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी दूसरे देश के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। वह इतने लंबे समय से खामोश क्यों थे?''

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ तीन तलाक मुद्दे पर तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। ■

भाजपा के बने 7 करोड़ नये सदस्य

कुल सदस्यों की संख्या 18 करोड़ हुई

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और "संगठन पर्व - सदस्यता अभियान 2019" कार्यक्रम की शानदार सफलता पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख श्री शिवराज सिंह चौहान, सह-प्रमुख श्री दुष्यंत गौतम, सह-प्रमुख श्री अरुण चतुर्वेदी और सह-प्रमुख श्रीमती शोभा सुरेंद्रन भी उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों द्वारा वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से 06 जुलाई 2019 को सदस्यता अभियान 2019 का शुभारंभ किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सिमसाबाद (तेलंगाना), पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुग्राम (हरियाणा), श्री राजनाथ सिंह जयपुर और श्री नितिन गडकरी ने नागपुर (महाराष्ट्र) से इस अभियान की उसी दिन शुरुआत की थी। इस अभियान का समापन 20 अगस्त 2019 को हुआ। बाढ़ और बारिश के कारण सदस्यता अभियान में मुश्किलें भी आईं, इसे कुछ दिनों के लिए बंद भी करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद यह सदस्यता अभियान काफी सफल रहा। चार राष्ट्रीय सदस्यता सह-प्रमुखों श्री दुष्यंत गौतम, श्री अरुण चतुर्वेदी, श्री सुरेश पुजारी और श्रीमती शोभा सुरेंद्रन ने देश के चार भागों का दायित्व संभाला जबकि राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रमुख श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे देश में प्रवास करते हुए लगभग सभी राज्यों में विभिन्न स्थानों में अनेकों कार्यक्रम किये।

सेना के रिटायर्ड अधिकारी, खिलाड़ी, लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा, महिलाओं सहित समाज के प्रतिष्ठित हस्तियों ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, यह इस बात का द्योतक है कि जन-मानस के मन में भाजपा के प्रति कितना अटूट विश्वास है।

श्री नड्डा ने कहा कि सदस्यता अभियान में पार्टी का संवैधानिक लक्ष्य 20% नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ना होता है, इस तरह हमें 11 करोड़ की सदस्यता के आधार पर लगभग 2 करोड़ 20 लाख नए सदस्य बनाने थे, लेकिन यह आंकड़ा लक्ष्य के तीन गुने से भी अधिक रहा। उन्होंने कहा कि हमें यह घोषणा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ऑनलाइन सदस्यता 5,81,34,242 रिकॉर्ड की गई जो हमारी पूर्व सदस्य संख्या की तुलना में 50% से भी अधिक है। ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से 62,34,967 नए सदस्य जुड़े हैं। साथ ही जहां-जहां सर्वर कमजोर था और मिस्ड कॉल को जहां हम डिजिटली कैप्चर नहीं कर पाए, उसे भी अब डिजिटली अपग्रेड किया जा रहा है। यदि ये सारी संख्या मिला दी जाय तो इस सदस्यता अभियान के दौरान बने पार्टी के नए सदस्यों की कुल संख्या 7 करोड़ के लगभग होगी। नए सदस्यों के जुड़ने के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के लगभग 18 करोड़ सदस्य हो गए हैं। विश्व में अभी केवल सात ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भाजपा के सदस्यों की संख्या से अधिक है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान की सफलता के लिए 1,85,965 विस्तारकों ने 7 दिन तक लगातार बूथ, मंडल और जिला स्तर पर कार्य किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं के अदम्य उत्साह, बजरंगी कर्मठता और भागीरथ प्रयास का ही सुफल है कि आज भाजपा का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामाख्या तक हो गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि यह केवल सदस्यता अभियान कार्यक्रम नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुसार इसका उद्देश्य जनता-जनार्दन को पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति भी जागरुक करना था, इसलिए जहां भी सदस्यता अभियान के कार्यक्रम आयोजित होते थे, वहां वृक्षारोपण अवश्य ही किया जाता था जिसमें कम से कम पांच फलदार एवं छायादार वृक्षों के पौधे अवश्य लगाए जाते थे। "संगठन पर्व - सदस्यता अभियान 2019" कार्यक्रम के तहत कुल 72,543 सदस्यता अभियान और वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किये गए और इस दौरान 19,66,074 फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए।

श्री नड्डा ने सदस्यता अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के सभी वर्गों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहा है और सदस्यता के ये आंकड़े इसके गवाह हैं। सेना के रिटायर्ड अधिकारी, खिलाड़ी, लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा, महिलाओं सहित समाज के प्रतिष्ठित हस्तियों ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, यह इस बात का द्योतक है कि जन-मानस के मन में भाजपा के प्रति कितना अटूट विश्वास है।

श्री नड्डा ने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष रुझान देखा गया। पश्चिम बंगाल में सदस्यता लक्ष्य जहां 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का निर्धारित किया गया था, वहीं यह आंकड़ा 80 लाख को पार कर गया है और अब यह एक करोड़ की ओर अग्रसर है। इसी तरह भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जम्मू-कश्मीर के करना विधानसभा के

6059 मतदाताओं ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गुजरात के पाटण जिले के चाणस्मा नगर के 14 बूथ के सभी 10,600 मतदाताओं ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सेवा बस्तियों में जाकर सदस्यता अभियान चलाया गया। जन संघ के समय से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया एवं उनके अनुभवों का लाभ भी लिया गया। जनता-जनार्दन का यह उत्साह साबित करता है कि भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ कुशल नेतृत्व देश के जन-जन के मन में भाजपा की विचारधारा पहुंचाने में सफल रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी में ही देश का भविष्य और भारत माता की सुरक्षा नजर आ रही है। सभी प्रदेशों ने अपने पूरे जोश के साथ लक्ष्य लिया और व्यवस्थित योजना बनाकर उस लक्ष्य को पूरा किया। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को एक संगठन पर्व के रूप में लेकर बड़े ही जोश व उत्साह में पूरा किया। पार्टी के सभी मोर्चों/प्रकोष्ठों ने सदस्यता अभियान में पूरी शक्ति के साथ काम क्या। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत है। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सदस्यता अभियान की पूरी टीम को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ■

धारा 370 की समाप्ति के बाद व्यापक संपर्क एवं जनजागरण अभियान

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन से भेंट

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के व्यापक संपर्क एवं जनजागरण अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन मल्होत्रा से नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर मुलाक़ात की।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने धारा 370 की समाप्ति और इससे जम्मू-कश्मीर के लिए खुलने वाले विकास के अनंत अवसर को रेखांकित करने के लिए भाजपा द्वारा चलाये जा रहे व्यापक संपर्क एवं जनजागरण अभियान के तहत 3 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन मल्होत्रा से उनके निवास स्थान 1, उमा शंकर दीक्षित मार्ग, चाणक्यपुरी (नई दिल्ली) में मुलाक़ात की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे।

श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की जनता के जीवन-स्तर में उत्थान लाने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की चर्चा की और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनोपयोगी कार्यों पर भी प्रकाश डाला।

ज्ञात हो कि धारा 370 के उन्मूलन की जानकारी देश के जन-जन तक पहुंचाने के लिए और इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में देश के प्रत्येक नागरिक को जम्मू-कश्मीर की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का बोध कराने हेतु भारतीय जनता पार्टी ने 01 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 तक पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क एवं जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

जनसंपर्क अभियान के तहत पूरे एक माह तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्र में वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, राज्यों के बड़े नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण द्वारा समाज जीवन के प्रमुख हस्तियों एवं प्रबुद्ध जनों से व्यक्तिगत मुलाक़ात कर धारा 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर में विकास की गति के तेज होने की चर्चा किया जाना सुनिश्चित हुआ है। ■

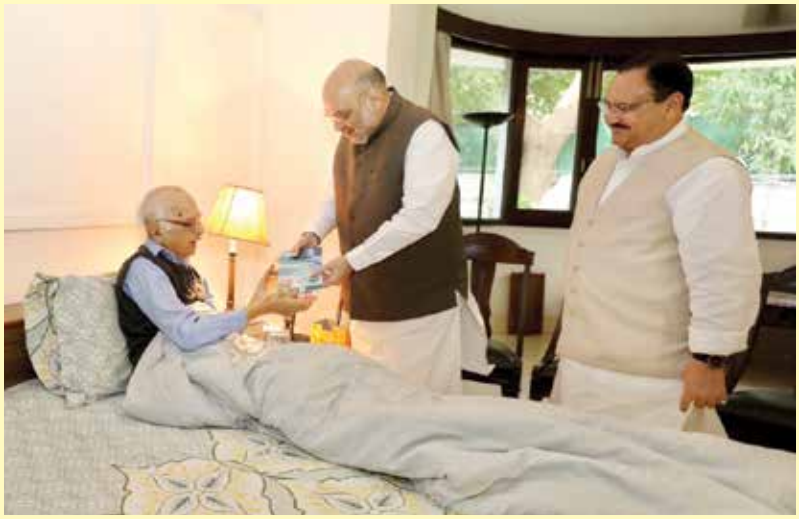

कोयला खनन और ठेका विनिर्माण में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें कोयला खनन और ठेका विनिर्माण में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश, एकल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं के लिए स्थानीय खरीद नियमों में ढील और दुकान खोलने से पहले ऑनलाइन कारोबार करने की अनुमति देना शामिल हैं।

एफडीआई नीति में सुधार से प्रमुख लाभ एवं प्रभाव

- एफडीआई नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप भारत ज्यादा आकर्षक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य बन सकेगा। इसका फायदा निवेश, रोजगार और विकास बढ़ाने में मिलेगा।
- कोयला क्षेत्र में कोयले की बिक्री के लिए कोयला खनन, इससे संबंधित प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग अवसंरचनाओं में स्वचालित रास्ते से 100% एफडीआई एक कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेगा।
- अनुबंध के माध्यम से विनिर्माण मेक इन इंडिया के उद्देश्य में समान रूप से योगदान देता है। अब अनुबंध विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति दी जा रही है, यह भारत में विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देने वाला होगा।
- वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट भाषण में एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को आसान बनाने की घोषणा की गई थी। एक आधार वर्ष में ज्यादा निर्यात वाली कंपनियों के लिए एक समान स्तर बनाने के अलावा इससे एसबीआरटी इकाइयों के लिए ज्यादा लचीलापन आएगा और परिचालन में आसानी होगी।
- पारंपरिक स्टोरों की शुरुआत से पहले ही ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से नीतियों को बाजार के मौजूदा तरीकों से मिलाया जा सकेगा। ऑनलाइन बिक्री से लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान, ग्राहक सेवा, प्रशिक्षण और उत्पाद कुशलता के क्षेत्र में भी रोजगार सृजन होगा।
- एफडीआई नीति में किए गए उपरोक्त संशोधनों का अर्थ देश में व्यापार को सुगमता प्रदान करने के लिए एफडीआई नीति को उदार और सरल बनाने से है और इससे निवेश, आय और रोजगार बढ़ाने में योगदान मिलेगा।

पृष्ठभूमि

एफडीआई आर्थिक विकास को गति देने वाला एक प्रमुख कारक है और देश के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वाले वित्त का स्रोत है। सरकार ने एफडीआई को लेकर एक निवेशक अनुकूल नीति बना रखी है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वचालित रास्ते से 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए एफडीआई नीति के प्रावधानों को हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उदार बनाया गया है। इनमें रक्षा, विकास संबंधी निर्माण, ट्रेडिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पावर एक्सचेंज, बीमा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, प्रसारण और नागरिक उड्डयन जैसे कुछ क्षेत्र शामिल हैं।

इन सुधारों ने पिछले पांच वर्षों में भारत में रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई के प्रवाह को आकर्षित करने में योगदान दिया है। भारत में वर्ष 2009-10 से 2013-14 की पांच साल की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक कुल एफडीआई 286 बिलियन डॉलर रहा है। वास्तव में, 2018-19 में कुल एफडीआई 64.37 बिलियन (अनंतिम आंकड़ा) डॉलर किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त किया गया सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ■

वायुसेना में शामिल हुए आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर

अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ायेगा

अमेरिका निर्मित आठ 'अपाचे एएच-64ई' लड़ाकू हेलीकॉप्टर तीन सितम्बर को भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए। इससे वायुसेना की युद्धक क्षमता में वृद्धि होगी। दरअसल, पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आयोजित समारोह में औपचारिक रूप से इन आठ अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयल चीफ मार्शल श्री बीएस धनोआ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बोइंग ने समारोह में हेलीकॉप्टर की प्रतीकात्मक चाबी वायुसेना को सौंपी।

'अपाचे एएच-64ई' दुनिया के सबसे उन्नत बहु-भूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिकी सेना इनका इस्तेमाल करती है। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं, जो बल की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएंगे।''

भारतीय वायुसेना ने 22 'अपाचे हेलीकॉप्टर' के लिए अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ सितम्बर 2015 में कई अरब डॉलर का अनुबंध किया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री बीएस धनोआ ने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस अपाचे 64-ई लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की अभियान और मारक क्षमताओं में वृद्धि करेगा।

पठानकोट वायुसेना स्टेशन में औपचारिक रूप से आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए आयोजित एक समारोह में उन्होंने यह बयान दिया।

श्री धनोआ ने कहा, "अपाचे 64-ई लड़ाकू हेलीकॉप्टर पुराने हो रहे एमआई-35 बेड़े की जगह लेंगे। कुल 22 अपाचे लिए जाने है और इसकी आखिरी खेप मार्च 2020 में मिलेगी।'' उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे।

श्री धनोआ ने कहा, "ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना की अभियान और मारक क्षमताओं में वृद्धि करेंगे।'' उन्होंने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर का भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल होना इसके आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री धनोआ ने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में दिन-रात तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम हैं। ■

विभिन्न राज्यों में वनीकरण के लिए केन्द्र ने 47,436 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि जारी की

वनीकरण को बढ़ावा देने और देश के हरित उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 29 अगस्त को सीएएमपीए को 47,436 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली में आयोजित राज्य के वन मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा, "वनों के लिए राज्य का बजट अप्रभावित रहेगा और हस्तांतरित की जा रही धनराशि राज्य के बजट के अतिरिक्त होगी तथा आशा है कि सभी राज्य इस धनराशि का उपयोग वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वानिकी कार्यकलापों में करेंगे, जिससे वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान अतिरिक्त कार्बन सिंक (यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण) होगा।" पर्यावरण मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीएएमपीए कोष का उपयोग वेतन के भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि के लिए नहीं किया जा सकता।

वन संपदा और देश की पारिस्थितिकी की सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा, "जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर इस धन का उपयोग किया जाएगा उनमें- क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, वन्यजीव प्रबंधन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक सम्पोषण, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने की कार्रवाइयों, वन में मृदा एवं आद्रता संरक्षण कार्य, वन्य जीव पर्यावास में सुधार, जैव विविधता और जैव संसाधनों का प्रबन्धन, वानिकी में अनुसंधान तथा सीएएमपीए कार्यों की निगरानी आदि शामिल हैं। ■

10 बैंकों के विलय से बनेंगे चार बड़े बैंक

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने देश में विश्वस्तरीय बैंक बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुये सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की 30 अगस्त को घोषणा की। इस पहल से न केवल आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, बल्कि देश को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी।

पिछले सप्ताह कर प्रोत्साहन उपायों की घोषणा करने वाली वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बैंकों के विलय का एलान किया। बैंकों में प्रस्तावित इस विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी। वर्ष 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 थी।

श्रीमती सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जायेगा। इस विलय के बाद पीएनबी भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जायेगा। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में जबकि आंध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक आफ इंडिया में विलय होगा। वहीं इलाहाबाद बेंक का विलय इंडियन बैंक में करने की घोषणा की गई।

सरकार 10 बैंकों में उनका पूंजी आधार मजबूत बनाने के लिये 52,250 करोड़ रुपये की पूंजी भी डालेगी। वित्त मंत्री ने कहा, ''हम घरेलू स्तर पर मजबूत और वैश्विक पहुंच वाले बैंक चाहते हैं ...इस विलय से उनके पास काफी संसाधन होंगे और कर्ज की लागत कम होगी।"

उन्होंने कहा कि विलय के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत, पर्याप्त पूंजी वाले वाले 12 बैंक होंगे। ''हम अगली पीढ़ी का बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।"

गौरतलब है कि श्रीमती सीतारमण ने पिछले सप्ताह करों में कटौती, बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी में सुधार, वाहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर सरकार का खर्च बढ़ाने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड कार्य में तेजी जैसे उपायों की घोषणा की।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों कोयला खनन, अनुबंध विनिर्माण, एकल खुदरा ब्रांड और डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाया। ■

गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा

6,286 करोड़ रुपये की सब्सिडी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 28 अगस्त को गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान चीनी मिलों के लिए 10,448 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात सब्सिडी प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 6,268 करोड़ रुपए का कुल अनुमानित व्यय होगा।

गन्ना सीजन 2019-20 के लिए एकमुश्त निर्यात सब्सिडी आवाजाही, उन्नयन तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य लागतों, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागतों और निर्यात पर ढुलाई शुल्कों सहित लागत व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात पर अधिकतम मान्य निर्यात मात्रा के लिए चीनी मिलों को आवंटित की जाएगी।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की बकाया राशि किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि सीधे तौर पर जमा कराई जाएगी और यदि कोई शेष बकाया राशि होगी तो चीनी मिल के खाते में जमा कराई जाएगी। कृषि समझौते की धारा 9.1 (डी) और (ई) के प्रावधानों तथा डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।

गन्ना सीजन 2017-18 (अक्तूबर-सितम्बर) और गन्ना सीजन 2018-19 के दौरान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से भिन्न, मौजूदा गन्ना सीजन 2019-20 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन चीनी का खुला भंडार होगा और सीजन के अंत में लगभग 162 लाख मीट्रिक टन भंडार होने का अनुमान है।

गौरतलब है कि चीनी के 162 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त भंडार से गन्ने के मूल्यों पर पूरे सीजन में प्रतिकूल दबाव पैदा होगा जिससे किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि के भुगतान में चीनी मिलों को कठिनाई होगी।

इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने हाल में 1 अगस्त, 2019 से एक वर्ष के लिए चीनी का 40 लाख मीट्रिक टन बफर भंडार तैयार किया है। हालांकि, 31 जुलाई, 2020 तक इस बफर भंडार और गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान बी-हेवी मोलेस/गन्ना रस से इथानॉल के उत्पादन द्वारा चीनी पर संभावित प्रभाव तथा दो महीने के लिए मानक भंडार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, चीनी का लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडार होगा, जिसका निपटारा निर्यात के माध्यम से करना होगा। ■

भारतीय जीवन पद्धति आज भी मार्गदर्शन कर सकती है

दीनदयाल उपाध्याय

हमें अपने जीवन के लिए परानुकरण की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपनी ही परंपरा का विचार करके अपनी जीवन रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र कोई सद्य उत्पन्न राष्ट्र नहीं है। हमारा सहस्रों वर्षों का इतिहास है, हमारी स्वयं की एक जीवन पद्धति है. जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है. पर हां, यह बात अवश्य है कि हज़ारों वर्षों के इतिहास में हमारे यहां जो जीवन पद्धति चली है। उसको हम आज वैसा का वैसा लेकर नहीं चल सकते। क्योंकि कुछ-न-कुछ युग का भी विचार करना पड़ेगा। यदि हम आज अपनी प्राचीन जीवन पद्धति को उसके असली रूप में अपनाना चाहें तो हम नहीं कर सकते। हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आ जाएंगी, परंतु हमारी जीवन पद्धति के पीछे जो तत्त्व हैं, हम उनको भुलाकर काम नहीं चला सकते। हमें उनके मूल रूप पर विचार कर उन्हें युगानुकूल बनाकर ग्रहण करना होगा।

जब हम तात्त्विक भूमिका के आधार पर खड़े होते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रश्न उठते हैं-जैसे मनुष्य क्यों पैदा होता है? उसका लक्ष्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए? हम जब भी किसी चीज़ का विचार करते हैं तो उसका विचार हमें इस आधार पर करना पड़ता है कि यह हमें किस लिए चाहिए?

जिसे रेलगाड़ी से जाना है, उसे तो उन्हीं साधनों का विचार करना पड़ेगा, जो उसकी यात्रा में आवश्यक हैं, परंतु जो कहीं जाने वाला नहीं, यदि वह यात्रा की आवश्यक वस्तुएं जुटाने का प्रयास करेगा तो यह ठीक नहीं होगा। इसी तरह हमारी जीवन की यात्रा है। यह यात्रा कहां से प्रारंभ होगी? कहां पर समाप्त होगी? इस पर विचार करने पर हम कुछ बातें पाते हैं। मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में कुछ चीजें करता है, कुछ नहीं करता। जो सुखकारक है वह करता है, जो सुखकारक नहीं वह नहीं करता है। अब प्रश्न उठता है कि 'सुख' है क्या? व्यावहारिक रूप से इसका विवेचन करने के लिए एक दूसरा प्रश्न उठता है कि यह सुख किसका? तो हम कहेंगे कि इंद्रिय का सुख; पर इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। केवल इंद्रिय सुख से ही काम नहीं चलता। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम इंद्रियों के सुख की वस्तु को त्याग देते हैं। उदाहरण के लिए हम भोजन करते हैं तो इंद्रिय सुख मिलता है, पर क्या हम शत्रु के यहां भोजन करेंगे? मानसिंह ने राणाप्रताप के यहां भोजन नहीं किया। हम सोचें, आख़िर क्यों नहीं किया? क्या वहां भोजन करने पर उसे इंद्रिय सुख नहीं मिलता? पर नहीं जो हमारा शत्रु है, जिससे हमारा मनमुटाव हो गया, जो अपना तिरस्कार करता है, अपना अपमान करता है, हम उसके यहां भोजन नहीं करते। इससे यह आवश्यक नहीं कि वहां भोजन करने से हमें इंद्रिय सुख नहीं मिलता; इंद्रिय सुख तो मिलता है, पर मन गवाही नहीं देता, मन को सुख नहीं मिलता। अतएव सुख का संबंध केवल इंद्रियों से ही नहीं, मन से भी है, मन के सुख को हम बुद्धि का सुख कहते हैं। बुद्धि को भी सुख की ज़रूरत होती है। बुद्धि को भी शक्ति की ज़रूरत होती है। एक पागल व्यक्ति कई बार हृष्ट-पुष्ट भी हो जाता है, कई बार उसे सुख भी होता है, परंतु उसकी बुद्धि अविकसित रहती है, उसकी बुद्धि में कष्ट रहता है और इस कष्ट के कारण उसे खाने-पीने के बाद भी चैन नहीं रहता, अर्थात् सुख मन का चाहिए, बुद्धि का चाहिए, और इसके आगे भी आत्मा का चाहिए। साधारणतया हम यह मानकर चलते हैं कि जब हम सुख की कल्पना करते हैं तो उसमें सभी इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख एवं आत्मा के सुख का संयोग होना चाहिए। जिन साधनों द्वारा ऊपर कथित चार तत्त्वों का पूर्ण विकास हो सके-वही हमें अपनाना चाहिए, जिससे सुख प्राप्त हो सके।

यदि हम आज अपनी प्राचीन जीवन पद्धति को उसके असली रूप में अपनाना चाहें तो हम नहीं कर सकते। हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आ जाएंगी, परंतु हमारी जीवन पद्धति के पीछे जो तत्त्व हैं, हम उनको भुलाकर काम नहीं चला सकते। हमें उनके मूल रूप पर विचार कर उन्हें युगानुकूल बनाकर ग्रहण करना होगा।

सुख प्राप्ति के लिए जिन साधनों को अपनाने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, उन्हें हमारे यहां 'पुरुषार्थ' कहा गया है। वह पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष-चार प्रकार का हो सकता है। ये चारों 'पुरुषार्थ' एक-दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थ पुरुषार्थ शरीर के लिए, धर्म पुरुषार्थ समाज के लिए, काम पुरुषार्थ कामना के लिए और मोक्ष पुरुषार्थ आत्मा के लिए-अर्थात् इन चारों पुरुषार्थों के समावेश से ही मनुष्य उन्नति कर सकता है। मनुष्य जब चारों के लिए प्रयत्नशील होगा, चारों की प्राप्ति का प्रयास करेगा तो उसे सुख मिल सकेगा। अब विचार होता है कि क्या कोई एक पुरुषार्थ ऐसा है, जिसकी प्राप्ति हो और शेष सारी चीजें स्वयं प्राप्त हो जाएं? अपने यहां अनेक लोगों ने इसके भिन्न उत्तर दिए हैं और सभी अपने-अपने उत्तर को महत्त्व देते हैं। जैसे कॉलेज में अर्थशास्त्र या तर्कशास्त्र पढ़ाने वाला अपने ही शास्त्र को प्रमुख शास्त्र कहता है, उसी तरह यहां भी कोई कहता है कि 'अर्थ' ही प्रमुख है तो कोई कहता है कि प्रमुख है तो 'काम'; किसी ने कहा कि धर्म प्रमुख है तथा किसी ने 'मोक्ष' को महत्त्व दिया। अनेक बार ऐसा

विवाद हुआ है कि हमें धर्म को आधार मानकर चलना चाहिए तो अर्जुन ने कहा कि अर्थ सबसे बड़ा है, उसके बिना धर्म नहीं चलेगा।

जब हम 'अर्थ' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र दोनों आ जाते हैं-यद्यपि यह दोनों मिलकर भी अर्थ पुरुषार्थ को पूरा नहीं करते। यद्यपि कुछ चीजें अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की हैं, किंतु उनका समावेश अर्थपुरुषार्थ में नहीं होता। अर्थ सब चीजों का आधार है, धर्म उसी पर टिकता है। अर्थ नहीं रहेगा तो धर्म नहीं चलेगा, अतएव राज की भी आवश्यकता, इसी आधार पर प्रतिपादित की गई है और उसी के आधार पर धर्म हमारे यहां चलता है।

यदि धर्म का समाज हो जाएगा, तो धर्म ही समाज हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में अर्थ होगा तो सभी चीजें ठीक होंगी। कहते हैं कि विश्वामित्र जब भूखों मरने लगे तो चांडाल के यहां से कुत्ते का जूठा मांस चोरी करके खाया। चांडाल के शंका करने पर उन्होंने कहा, इसमें अधर्म कुछ नहीं है। सब धर्मों का आधार प्राण रक्षा है। सुख प्राणों को तृप्त करने वाली चीज़ को कहते हैं। प्राण को धर्म का आधार कहा और प्राण रक्षा अर्थबाहुल्य से ही संभव है। जिसके पास अर्थ नहीं उसको मां-बाप, भाई-बंधु कोई नहीं पूछते, पर इस अर्थ में यदि धर्म का भाव छोड़ दिया तो अनर्थ हो जाना स्वाभाविक है।

राज्य केवल इसलिए आया कि वह धर्म को चलाकर चले। शास्त्रकारों ने अर्थ को सबका मूल कहा। कुछ ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी वस्तु काम है, यह न रहा तो सब चीज़ बेकार है। विदुर ने कहा कि अर्थ बंधन कारक है, धर्म बंधन कारक है और काम तो बंधन कारक है ही। सबसे बड़ी वस्तु मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, फिर कोई कामना भी नहीं रहती। इसलिए निष्काम भाव से मोक्ष पा लेना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। विदुर के इस विवाद का अंत युधिष्ठिर ने किया। उन्होंने कहा कि कोई भी एक पुरुषार्थ बड़ा नहीं है। चारों को जो एक साथ लेकर चलेगा, वही पुण्य है। एक को पाने का जो प्रयास करेगा, वह अधूरा है और एक को प्राप्त करने का प्रयास करने वाला पापी भी है। एक को विचार करना मानव जीवन के टुकड़े करना है, किंतु यह सत्य है कि मानव-जीवन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कई बार शास्त्र खंड-खंड करके विचार करते हैं, जिसके कारण ग़लती होती है; क्योंकि वह विचार जीवन के एक अंग के बारे में रहता है। पश्चिम में इसी प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके विचार हुआ। 'पोलिटिकल' है तो केवल 'मैन इज़ ए पोलिटिकल बीइंग' का विचार करेगा। 'इकोनॉमिक्स' में 'इकोनॉमिक मैन' की कल्पना की गई, जिसका एक ही जीवन है और जिसमें अर्थशास्त्र की क्रियाएं एवं सिद्धांतों का ही विचार होता है। जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं। आर्थिक क्रियाओं के पीछे केवल अर्थ एवं उपयोगिता के सिद्धांत काम नहीं करते, वरन् कुछ और भी भावनाएं काम करती हैं, जैसे अपने देश में बनी वस्तु महंगी होने पर भी, कम उपयोगी होने पर भी ख़रीदी जाती है। इसी प्रकार जब बालक बढ़ जाता है तो उसकी इच्छित वस्तु ख़रीदनी ही पड़ती है, चाहे उपयोगिता की दृष्टि से न्यून ही क्यों न हो। ऐसे समय में यदि हम अर्थशास्त्र का ही विचार करें तो अनर्थ हो सकता है। वास्तविकता यह कि हमें मानव-दृष्टि से विचार करना चाहिए। मनुष्य की अनेक भावनाएं हैं। केवल एक मनोवृत्ति का ही विचार न करें, तब तो चारों पुरुषार्थों को समान मानकर हमें चारों की उपासना करनी चाहिए।

इन चारों का आधार स्तंभ यदि कोई हो सकता है तो वह धर्म ही है। धर्म से अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है। यद्यपि धर्म, अर्थ एवं काम पर टिकता है, पर यदि इसमें से धर्म को छोड़ दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और यदि उसमें धर्म जोड़ दिया जाए तो वही अर्थ हमारे काम की प्राप्ति का साधन होगा। धर्म, अर्थ एक-दूसरे के पोषक होते हैं। मनु ने धर्म के दस लक्षण गिनाए हैं-धृति, क्षमा, दमोस्तेयम्। भूमि इन्हीं के आधार पर अर्थ की प्राप्ति होती है। धृति (धैर्य) जो कि धर्म का बिल्कुल आधार है, मानव इसी धृति को आधार मानकर चलते हैं। 'धारणात् धर्म इत्याहुः' में धृति पहली चीज़ कही गई है, जो कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। धनार्जन में भी धैर्य रखना आवश्यक होता है, जो धैर्य रखकर प्रयत्न नहीं कर सकता, वह पैसा भी कमा नहीं सकता।

धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। जो व्यवहार में अच्छा है और व्यवहार में कोई बात आ गई तो गम खा लेगा, लड़ेगा नहीं, ऐसा क्षमाशील है-शायद क्षमा व्यापार वृद्धि एवं अर्थार्जन के लिए भी आवश्यक है। जो दूसरों के अवगुण को क्षमा करके चल नहीं सकता, वह अर्थार्जन भी नहीं कर सकता। दुकान पर आने वाला ग्राहक चाहे ग़लत बोल बोले, दुकानदार को भला-बुरा कहे, दस रुपए की वस्तु के दो रुपए लगाए, पर अच्छा दुकानदार इससे कभी बुरा नहीं मानता। धर्म का तीसरा लक्षण सत्य है। सत्य का अर्थ है, मन-वचन-कर्म की एकता। आजकल लोग सोचते हैं कि व्यवसाय में असत्य ही चलता है, पर यह ग़लत है। सत्य को यदि जीवन से निकाल दिया जाए तो कुछ काम नहीं चल सकता। पारस्परिक विश्वास सत्य के आधार पर ही संभव है। इस सत्य से हमारा व्यवसाय भी बढ़ता चला जाएगा। हम अधिक धनार्जन करने में सफल हो सकेंगे। यदि हमने सत्य का पालन नहीं किया तो व्यवस्था में पूर्ण गड़बड़ी आ जाएगी। आज की जो व्यावहारिक कठिनाइयां देखते हुए व्यवसायी लोग भी मिलावट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर धार्मिक भावना लुप्तप्राय हो गई है। इन सब बातों का संबंध हमसे है, अतएव हमें धर्म के आधार पर चलना होगा; अपने जीवन में सत्य, धर्म को सम्यक् प्रकार से प्रतिष्ठित करना होगा। सारांश यह कि धर्म से अर्थ का घनिष्ठ संबंध है तथा धर्म से हर अर्थ की प्राप्ति संभव है। दूसरी ओर अर्थ से धर्म टिकता है। यदि अर्थ प्रचुर मात्रा में हुआ तो धर्म का ठीक प्रकार से पालन होता है अन्यथा इसके अभाव में लोग परस्पर लड़ते हैं, अधर्म होता है। यदि गाड़ी में पर्याप्त स्थान है तो कोई गड़बड़ी नहीं मचती, पर यदि जगह का अभाव हुआ तो गड़बड़ी मचती है, उठने वालों को उतरना मुश्किल हो जाता है, फिर वह तो उतरेगा ही-किसी के पांव पर पांव रखकर; किसी को कुचलते हुए उतरते हैं। अब अभाव के कारण 'क्यू हैबिट' का विचार आता है। भारत में 'क्यू हैबिट' नहीं है, पर जहां अभाव नहीं, वहां 'क्यू हैबिट' की क्या आवश्यकता? क्यू हैबिट' की आवश्यकता अभाव में होती है। जब सबके पास पर्याप्त खाने को है तो राशनिंग की क्या आवश्यकता? अतएव हमारे यहां जो नियम बने, वह समृद्धि काल को याद दिलाते हैं, अर्थात् जिस समय हमारे यहां नियम बने, उस समय देश समृद्ध था। ■

-पाञ्चजन्य, अक्तूबर 10, 1960(क्रमशः)

प्रधानमंत्री ने किया 'फिट इंडिया' मुहिम का शुभारंभ

जो फिट है, वह हिट है और बॉडी फिट तो माइंड हिटः नरेंद्र मोदी

वीरता और फिटनेस को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को 'फिट इंडिया आंदोलन' का शुभारंभ किया, लेकिन कहा कि इसे सरकारी नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाकर देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा।

महान हाकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत की सांस्कृतिक विरासत में फिटनेस के महत्व की बानगी पेश करते रंगारंग कार्यक्रम के बीच श्री मोदी ने कहा, "आज का दिन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का दिन है जो दुनिया के मंच पर तिरंगे का परचम लहरा रहे हैं लेकिन फिट इंडिया का विस्तार खेलों से आगे तक होना चाहिये।"

उन्होंने कहा, "युवा खिलाड़ियों को मिलने वाले पदक उनकी तपस्या के परिचायक तो हैं ही, लेकिन यह नये भारत के नये जोश और नये आत्मविश्वास का भी पैमाना है। पिछले पांच साल में खेलों के लिये जो बेहतर माहौल बना है, उसका फायदा अब मिल रहा है।"

श्री मोदी ने फिटनेस को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताते हुए कहा, "हमारे पूर्वज 'त' से तलवार पढ़ते थे और सीमित सोच वाले लोगों के कारण परंपराओं से हम इस तरह अलग हो गए कि लगने लगा कि 'त' से तलवार पढाने से बच्चों की मनोवृत्ति हिंसक हो जायेगी। इसलिये 'त' से तरबूज हो गया। इससे वीरता, शारीरिक सामर्थ्य और फिटनेस को चोट पहुंची।"

उन्होंने कहा, "फिटनेस परिवार, समाज और देश की सफलता का मानक होना चाहिये। स्वच्छ भारत आंदोलन की तरह फिट इंडिया आंदोलन का प्रचार-प्रसार भी देश के कोने कोने में होना चाहिये। यह एक मंत्रालय का नहीं, देश का आंदोलन बने। देश के हर गांव, पंचायत और स्कूलों तक इसे पहुंचाना होगा।"

श्री मोदी ने बदलती जीवनशैली को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिये जिम्मेदार बताते हुए कहा कि मोबाइल एप पर टिकी फिटनेस से काम नहीं चलने वाला।

उन्होंने कहा, "कुछ दशक पहले तक हम पैदल चलने, साइकिलिंग या शारीरिक श्रम से पीछे नहीं हटते थे लेकिन तकनीक ने हमें आलसी बना दिया। बीमारियों की संख्या बढती जा रही है जो चिंता का सबब है और इससे निजात पाने के लिये हमें जीवनशैली बदलनी होगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बदलावों के लिये समूचे देश को प्रेरित करने का नाम ही 'फिट इंडिया आंदोलन' है। उन्होंने दुनिया के अग्रणी देशों में चल रहे फिटनेस अभियान का हवाला देते हुए कहा, "चीन 'हेल्दी चाइना 2030' के लिये मिशन मोड में काम कर रहा है। आस्ट्रेलिया ने 2030 तक अपने 15 प्रतिशत नागरिकों को व्यायाम में सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन में 2020 तक पांच लाख नये लोग व्यायाम से जुड़ेंगे, जबकि अमेरिका 2021 तक करीब 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ेगा।"

श्री मोदी ने कहा, "दुनिया के सभी देशों में जागरूकता बढ़ी है। भारत में भी कुछ लोगों को नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को फिट होना होगा जबकि श्रेष्ठ और सशक्त भारत बनेगा।"

उन्होंने लोगों से अपने पसंदीदा आइकन का अनुसरण करने का आहवान किया। उन्होंने कहा, "आपके जो भी आदर्श हों चाहे खिलाड़ी, बालीवुड स्टार या उद्योगपति, सफल लोगों का आम स्वभाव फिटनेस पर उनका भरोसा है। जो फिट है, वह हिट है और बाडी फिट तो माइंड हिट। मैं फिट तो इंडिया फिट को अपना मूलमंत्र बनाना होगा।"

इस मौके पर खेलमंत्री श्री किरेन रीजीजू ने इस आंदोलन को जन भागीदारी से नयी ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, "पहली बार देश में फिटनेस को लेकर इतनी बड़ी मुहिम शुरू की गई है जो प्रधानमंत्री की कल्पना और सशक्त भारत के सपने का अहम अंग है। इसे नयी बुलंदियों तक ले जाना होगा।"

इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में फिटनेस के महत्व को पंजाब के गतका, पूर्वोत्तर के थांग टा, केरल के कलारीपायट्टू मार्शल आर्ट के जरिये प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही भरतनाट्यम, भांगड़ा, बीहू, गरबा जैसे नृत्यों के मार्फत कलाओं में फिटनेस की बानगी पेश की गई। वहीं खोखो, स्टापू, गिल्ली डंडा, कंचे, कुश्ती, मलखम्ब, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों के जरिये बच्चों में फिटनेस के प्रति जागरूकता जगाने के लिये रंगारंग प्रस्तुति दी गई।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन और कृषि व किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त तमाम खिलाड़ी, कोच आदि इस आयोजन में शामिल हुए। ■

नहीं रहे अरुण जेटली

(28 दिसम्बर 1952 - 24 अगस्त 2019)

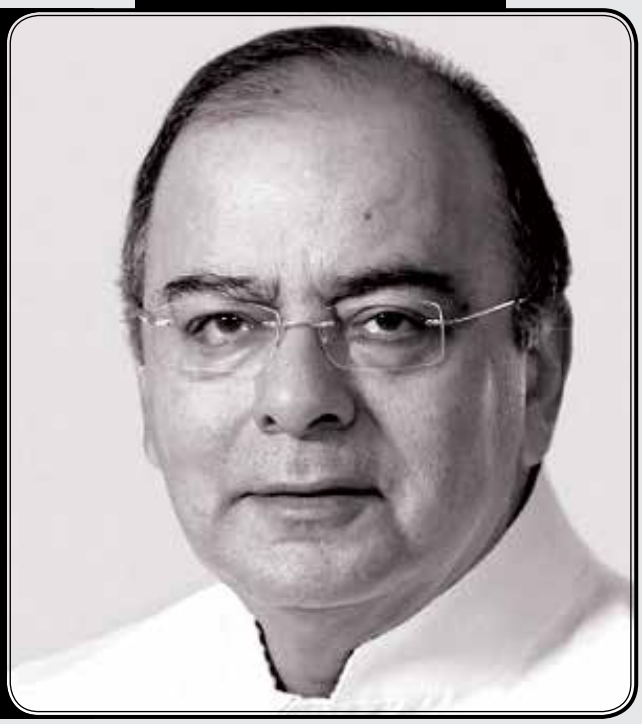

देश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली नहीं रहे। उनका निधन 24 अगस्त को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। वे 66 वर्ष के थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश-विदेश के प्रमुख नेतागण व व्यक्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया।

श्री अरुण जेटली कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के नए मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि वह स्वास्थ्य कारणों से नई सरकार में मंत्री नहीं बनना चाहते। इलाज एवं स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

दिल्ली स्थित निगमबोध घाट पर हुए श्री जेटली के अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति सर्वश्री वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद विजय गोयल और विनय सहस्रबुद्धे, कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कपिल सिब्बल, राकांपा नेता पी प्रफुल पटेल समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों क्रमशः सर्वश्री देवेंद्र फड़णवीस, विजय रुपाणी, बी एस येदियुरप्पा, नीतीश कुमार, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अरविंद केजरीवाल भी अंतिम संस्कार में मौजूद थे।

विदेश की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री जेटली को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह कल्पना नहीं कर सकते कि वह भारत से दूर बहरीन में है, जब उनका ''प्रिय दोस्त'' और पार्टी सहयोगी नयी दिल्ली में उन्हें छोड़कर चला गया।

श्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, "मैंने एक अहम दोस्त खो दिया है, जिन्हें दशकों से जानने का सम्मान मुझे प्राप्त था। मुद्दों पर उनकी समझ बहुत अच्छी थी। वो हमें अनेक सुखद स्मृतियों के साथ छोड़ गए। हम उन्हें याद करेंगे।"

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी लिखा कि बीजेपी और अरुण जेटली के बीच एक ना टूटने वाला बंधन था। उन्होंने ट्वीट किया, "एक तेजस्वी छात्र नेता के तौर पर उन्होंने आपातकाल के समय हमारे लोकतंत्र की सबसे आगे होकर रक्षा की थी। वो हमारी पार्टी के लोकप्रिय चेहरा थे। जिन्होंने समाज के अलग-अलग तबकों तक पार्टी के कार्यकर्मों और विचारों को स्पष्ट रूप से पहुंचाया।"

जीवन परिचय

श्री अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को नई दिल्ली में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल में हुई। 1973 में इन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान वे पढ़ाई के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेते

श्री अरुण जेटली के निधन से बहुत दुःखी हूं। उन्होंने साहस और गरिमा के साथ लंबी बीमारी से जंग लड़ी। एक प्रतिभाशाली वकील, अनुभवी सांसद और प्रतिष्ठित मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान दिया।

— **रामनाथ कोविंद**, राष्ट्रपति

वह दशकों तक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे। जब मैं पार्टी अध्यक्ष था तो उन्हें कोर टीम में शामिल किया गया था। वह जल्द ही पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बन गए।

— **लालकृष्ण आडवाणी**, वरिष्ठ भाजपा नेता

जेटली जी को हमेशा अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने और पटरी पर लाने के लिए याद किया जाएगा। बीजेपी को अरुण जी की कमी खलेगी। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
अरुण जेटली जी ने कई क्षमताओं में देश की सेवा की और वो सरकार और पार्टी के लिए एक संपत्ति की तरह थे। हर मुद्दे पर उनकी गहरी समझ होती थी। उन्होंने अपने ज्ञान और बात करने के स्पष्ट तरीके की बदौलत कई दोस्त बनाए।

— **राजनाथ सिंह**, केंद्रीय रक्षा मंत्री

रहे। श्री जेटली 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए।

आपातकाल (1975-77) के दौरान वे 19 महीने जेल में रहे। 1980 में भाजपा में शामिल हो गए और 1991 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपनी जगह बनाई। श्री अरुण जेटली 1989 में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने।

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को सूचना प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया गया। इसके अलावा पहली बार एक नया मंत्रालय बनाते हुए उन्हें विनिवेश राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया गया। 23 जुलाई 2000 को जेटली को कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2014-19 के कार्यकाल के दौरान देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। इनके समय में जीएसटी, नोटबंदी, जनधन योजना, जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। महंगाई को काबू में रखने का श्रेय भी श्री जेटली को जाता है।

श्री अरुण जेटली को दो बार रक्षा मंत्रालय का प्रभार मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त था। मई 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद इन्हें वित्त और रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया। वे 2014 में रक्षा मंत्री रहे, लेकिन बाद में श्री मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बनाए गए। लेकिन श्री पर्रिकर के गोवा का मुख्यमंत्री बनने के बाद जेटली को 2017 में दोबारा यह प्रभार दिया गया।

अरुण जेटली के निधन से मैंने एक बहुमूल्य मित्र खो दिया है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन पर दुःख व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, "अरुण जेटली जी असाधारण राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी और कानून के जानकार थे। वह स्पष्टवादी नेता थे जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जाना बेहद दुखद है। मैंने उनकी पत्नी संगीता जी और पुत्र रोहन से बात की है, और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ओम शान्ति।"

श्री मोदी ने कहा कि जीवन से भरपूर, हाजिरजवाब, विनोदी स्वभाव के और प्रतिभावान, अरुण जेटली जी को समाज के हर वर्ग के लोग चाहते थे। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारत के संविधान, इतिहास, शासकीय नीति, शासन और प्रशासन के बारे में गहरी जानकारी रखते थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान अरुण जेटली जी ने अनेक मंत्रालयों में जिम्मेदारियां संभाली, जिससे वह भारत के आर्थिक विकास, हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने, लोगों के अनुकूल कानून बनाने और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में योगदान देने में सक्षम हुए।

उन्होंने कहा कि भाजपा और अरुण जेटली जी का अटूट बंधन था। जोशीले छात्रनेता के रूप में आपातकाल के दौरान वह लोकतंत्र की रक्षा में अग्रणी रहे। वह हमारी पार्टी के चहेते थे, जो पार्टी के कार्यक्रमों और विचारधारा की समाज में विस्तृत पहुंच बना सकते थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली के निधन से मैंने एक बहुमूल्य मित्र खो दिया है मुझे उन्हें कई दशकों से जानने का गौरव प्राप्त था। मुद्दों पर उनकी अंतरदृष्टि और उनकी बारीक समझ की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने सम्मानित जीवन जिया, वह हमारे साथ अनेक अच्छी स्मृतियां छोड़ गए हैं। उनकी कमी हमेशा खलेगी।

वे एक आदर्श कार्यकर्ता और लोकप्रिय जन-प्रतिनिधि थे: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने शोक संदेश में कहा कि पूर्व वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्री अरुण जेटली जी के निधन से मन अत्यंत दुःखी और मर्माहत है। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनके रूप में मैंने न सिर्फ संगठन का एक वरिष्ठ नेता खोया है, बल्कि परिवार का एक ऐसा अभिन्न सदस्य भी खोया है जिनका साथ और मार्गदर्शन मुझे वर्षों तक प्राप्त होता रहा। श्री जेटली ने एक प्रखर वक्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता, लोकप्रिय जन-प्रतिनिधि, कर्मठ मंत्री एवं कुशल प्रशासक के रूप में देश की राजनीति में एक अलग छाप छोड़ी है।

उन्होंने कहा कि खुशमिजाज व्यक्तित्व वाले जेटली जी से मिलना और उनसे विचार-विमर्श करना सभी के लिए एक सुखद अनुभव होता था। आज उनके जाने से भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी रिक्तता आयी है जिसकी भरपाई होना जल्दी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2014-19 के कार्यकाल के दौरान देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी और प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की परिकल्पनाओं को जमीन पर उतारा और हिन्दुस्तान को विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया।

श्री शाह ने कहा कि काले धन पर कार्यवाही की बात हो, एक देश-एक कर 'जीएसटी' के स्वप्न को साकार करने की बात हो, नोटों के विमुद्रीकरण की बात हो या आम आदमी को राहत पहुंचाने की बात, उनके हर निर्णय में देश और देश की आम जनता का कल्याण निहित था। देश उन्हें उनके अत्यंत सरल, संवेदनशील, सशक्त, ऊर्जावान एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए सदैव याद रखेगा।

उन्होंने कहा कि अरुण जी ने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए थे। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी संयोजक रहे। श्रद्धेय अटल बिहार वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली भाजपा-नीत एनडीए सरकार में कई मंत्रालयों को जिम्मेदारी से संभाला। 2009 से 2014 तक वे राज्य सभा में विपक्ष के नेता रहे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में उन्होंने 2014-19 के दौरान वित्त मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के

दायित्वों को संभाला और कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने अद्वितीय अनुभव और विरले क्षमता से अरुण जी ने संगठन और सरकार में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में श्री जेटली ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो देश में एक 'ईमानदार अर्थव्यवस्था' को स्थापित करने में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ज के 'न्यू इंडिया' के स्वप्न को साकार करने के लिए कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया।

श्री शाह ने कहा कि श्री जेटली पार्टी के कुशल रणनीतिकार भी थे। चुनावों के दौरान उन्होंने हर समय अपनी कुशल सांगठनिक क्षमता के परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। एक प्रतिष्ठित कानूनविद के रूप में भी उनका कोई सानी नहीं था। पार्टी और देश सदैव उनके योगदान के लिए उनका ऋणी रहेगा।

उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं, भाजपा नेतृत्व और व्यक्तिगत तौर पर भी उनके परिजनों, समर्थकों व शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भावुक हृदय से श्री अरुण जेटली जी को अंतिम विदाई दे रहा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को इस गहरे आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ॐ शांति शांति शांति!

अरुण जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर दिया: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली के निधन पर दुःख व्यक्त किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, "भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी का निधन मेरे लिए अत्यंत असहनीय है। अरुण जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज और भाजपा को समर्पित कर दिया। विगत कई वर्षों में हर विषय पर उनका मार्गदर्शन मिला। ईश्वर पुण्य आत्मा को शान्ति प्रदान करें और एवं शोकाकुल परिजनों को शक्ति प्रदान करें।

अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, "अरुण जी के जाने से भारतीय राजनीति में जो शून्य आया है, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। संसद के अंदर उनके प्रभावी भाषणों की गूंज, कठिन से कठिन समस्या के समय भी उनका मुस्कराता हुआ चेहरा सदैव हमारे साथ रहेगा। अरुण जी के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ॐ शांति शांति।

ट्वीट में श्री नड्डा ने कहा, "संगठन एवं सरकार में अनेक दायित्व पर रहते हुए श्री अरुण जेटली जी राष्ट्र सेवा में समर्पित रहे। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, देश की रक्षा व्यवस्था को मज़बूत करना हो, प्रत्येक जगह पर देश को विश्व में अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने में उनकी भूमिका अतुलनीय है। ■

जेटली का निधन राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति: एम. वेंकैया नायडू

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली के निधन पर दुःख व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि श्री जेटली एक उत्कृष्ट सांसद, कानून के जानकार, बुद्धिजीवी, एक सक्षम प्रशासक और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। श्री जेटली ने देश में जीएसटी की शुरुआत करने और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं अपने पुराने मित्र और निकटतम सहयोगियों में से एक श्री अरुण जेटली के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। उनका निधन राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मेरे पास दुःख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट सांसद, कानून के जानकार, बुद्धिजीवी, एक कुशल प्रशासक और बेहद ईमानदार श्री जेटली ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडलों में केन्द्रीय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कुशलता से संभालकर विशिष्टता हासिल की। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्राप्त था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री जेटली ने देश में जीएसटी की शुरुआत करने और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर जनता के साथ संवाद कायम किया। वह जटिल से जटिल मुद्दों को साधारण तरीके से सुलझा लेते थे।

शोक संदेश

अरुण जेटली के असामयिक निधन से गहरा दुःख हुआ है। एक दिन पहले ही एम्स जाकर उनसे मुलाकात की थी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की थी। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

– **प्रणब मुखर्जी**, पूर्व राष्ट्रपति

अरुण जेटली एक प्रमुख वकील, बेहतर वक्ता, अच्छे प्रशासक और बेहतर सांसद थे। दुःख की इस घड़ी में परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

– **मनमोहन सिंह**, पूर्व प्रधानमंत्री

एक प्रतिभाशाली और विद्वान राजनेता अब हमारे बीच नहीं रहा। जेटली ने बहुत कम उम्र में अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

– **मोहन भागवत**, संघ प्रमुख

देश ने प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता और कद्दावर नेता को खो दिया। अरुण जेटली के निधन से निजी तौर पर मैं बेहद दुःखी हूं। उनके परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना जाहिर करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं।

– **रंजन गोगोई**, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

मैंने उन्हें तब से जानता हूं जब वह विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता थे। उन्होंने भाजपा के विस्तार में बहुत योगदान दिया है। भाजपा अध्यक्ष रहने के दौरान विभिन्न मामलों पर उनके सुझाव लेता था। वह पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पित थे।

– **नितिन गडकरी**, केंद्रीय मंत्री

अरुण जेटली लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे। सांसद और मंत्री के रूप में लोगों के लिए उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमता और संवाद करने की कला हर रूप में दिखाई देती थी। वह भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम थे।

– **सोनिया गांधी**, कांग्रेस नेता

अरुण जेटली जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनके परिवार के लिए शोक व्यक्त करता हूं। अपने छात्र जीवन से संसद तक दशकों से हम एक दूसरे से परिचित रहे।

– **सीताराम येचुरी**, माकपा महासचिव

श्री अरुण जेटली के जाने से हुई क्षति को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हममें से कइयों के मेंटर, मार्गदर्शक और एक नैतिक सहयोग और ताक़त देने वाले शख्स। एक बड़े दिल वाले उम्दा इंसान। हर वक्त किसी की भी मदद के लिए तैयार। उनकी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, निपुणता का कोई मुक़ाबला नहीं कर सकता।

— **निर्मला सीतारमण**, वित्त मंत्री

पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन (नेडा)

'पूरे देश में नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है और सिर्फ असम ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों समेत पूरे देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। गत 9 सितम्बर को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन (नेडा) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने अनुच्छेद 371 में किसी तरह का बदलाव नहीं होने का आश्वासन दिया।

पूर्वोत्तर भारत के विकास में सभी सहयोगी दलों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूर्वोत्तर भारत सिर्फ 'नार्थ इस्ट' भर नहीं है, जैसा कि 2014 के पहले देखा जाता था, बल्कि देश के विकास के लिए 'न्यू इंजिन ऑफ ग्रोथ' है।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के विकास को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का नतीजा है कि 2014 के बाद इस क्षेत्र में विकास की गतिविधियों में तेजी आई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आन वाले समय में यह क्षेत्र व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करेगा और

दिल्ली के युवा गुवाहाटी और मेघालय में नौकरी की तलाश में आएंगे। श्री शाह ने कहा कि भारत के कुल वन क्षेत्र के 26 फीसदी हिस्से के साथ पूर्वोत्तर के राज्य एक तरह से देश के फेफड़े की तरह हैं।

अनुच्छेद 370 के बाद 371 में बदलाव की बात पर श्री शाह ने कहा कि संविधान में 370 को अस्थायी रूप में जोड़ा गया था। वहीं 371 के प्रावधान स्थायी हैं और यह पूर्वोत्तर राज्यों का अधिकार है। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए इसे बनाए रखा जाएगा। ■

सियासी सफर के साथी का जाना

एम. वेंकैया नायडू

इस माह की 11 तारीख को दिल्ली के एक अस्पताल में अपने पुराने प्रिय मित्र अरुण जेटली से मिलने गया तो मुझे उम्मीद थी कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे। उनका हाथ मेरे हाथों में था, उन्होने मुझे देखा और यह जताया कि सब ठीक हो जाएगा। यह उम्मीद नहीं थी कि यह उनके साथ आखिरी बार हाथ मिलाना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अरुण जेटली इतनी जल्दी हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। मैं इस सच्चाई से सामंजस्य नहीं बना पा रहा हूं कि वे अब कभी भी काम पर वापस नहीं आएंगे और हमेशा की तरह जरूरत के वक्त, मैं उन्हें तलाश नहीं पाऊंगा।

मैंने अपने कॉलेज के दिनों में एक साथ आने के बाद 40 वर्षों से उनके प्रबुद्ध परामर्श और बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया है। हम पहली बार 1974 में छात्र यूनियन अध्यक्षों के सम्मेलन में मिले, जहां जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मैं आंध्र विश्वविद्यालय से था। तब से हम दोनों आपसी सम्मान और निर्भरता के एक मजबूत बंधन से समन्वित अपनी राजनीतिक यात्रा के सुख-दुःख के साथी रहे हैं। मैं इस तरह एक प्रिय मित्र के असामयिक निधन से टूट गया हूं, क्योंकि भाग्य ने फिर से अपनी क्रूरता दिखाई है।

अरुण जेटली बहुमुखी प्रतिभा से समन्वित और बहुआयामी पांडित्य के धनी थे। 66 साल के जेटली को समकालीन भारत के व्यापक रूप से स्वीकृत राजनीतिज्ञों में से एक के रूप में जाना जाता है। जेटली अपने विचारों की स्पष्टता, दृढ़ विश्वास, प्रभावी सम्प्रेषण कौशल और प्रासंगिकतापूर्ण प्रस्तोता के रूप में अग्रणी रहे। वह पार्टी और सरकार के लिए समकालीन युग के सबसे प्रभावी प्रवक्ता के रूप में उभरे। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महती ओजस्वी आवाज खो दी है।

लंबे समय तक कानून के अध्ययन और अभ्यास और उनकी कुशाग्रता ने जेटली को योग्यता के आधार पर तर्कपूर्ण जीत प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की। राजनीतिक दायरे के पार उनके राजनीतिक साथियों ने यह उदारतापूर्ण स्वीकार किया कि कोई संभवतः उनके सभी बिंदुओं पर सहमत न हो, लेकिन वह उनके प्रबल दृष्टिकोण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। वे इस व्यापक मान्यता के योग्य थे। जेटली अपने उन महत्वपूर्ण मंतव्यों के लिए सभी के लिए यादगार रहेंगे, जिन्हें वे सार्वजनिक और संसदीय संभाषण के रूप में सभी प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुत किया करते थे। विभिन्न मुद्दों पर उनके नियमित ब्लॉग, सूचनात्मक और सुरुचिपूर्ण हुआ करते थे।

जेटली की बहुआयामी प्रतिभा को तेजी से पहचान मिली। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद जेटली 1977 में आपातकाल के बाद स्थापित जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। तब से वे हमारे देश के राजनीतिक भंवरों में एक स्थिर व्यक्तित्व के रूप में विद्यमान रहे हैं। वे 1991 से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, जो कई मायनों में पार्टी के लिए उनके योगदान की साक्षी है। जब मैं पार्टी अध्यक्ष था, तो मैंने उन्हें सुषमा स्वराज के साथ पार्टी के संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया, जो पार्टी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय था। मुद्दों की अपनी समझ और प्रलेखन कौशल के साथ जेटली ने इन सभी वर्षों में अपनी पार्टी के लिए कई संकल्पों को लेखबद्ध किया।

जेटली ने उन सभी मंत्रालयों में अपनी खुद की एक छाप छोड़ी जो उन्होंने कई वर्षों में संभाले थे जिनमें वित्त और कॉर्पोरेट मामले, रक्षा, वाणिज्य और उद्योग, जहाजरानी, विनिवेश और सूचना और प्रसारण थे। उन्होंने धन शोधन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनों के अलावा जीएसटी अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता सहित आर्थिक परिवर्तन की भरपाई के लिए कई विधानों को संचालित किया था। उन्होंने एक नाजुक समय में 2014-19 के दौरान देश के वित्त मंत्री के रूप में की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बड़ी निपुणता से संभाला था।

जब 2009 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता का मुद्दा सामने आया, तो उनके द्वारा इसे स्वीकार किए जाने से पहले हम दोनों ने इसके लिए एक-दूसरे को चुने जाने पर जोर दिया था। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में उच्च सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में अध्यक्ष रूप में मेरे लिए वे एक बड़े समर्थन के रूप में थे। वे एक उत्कृष्ट रणनीतिकार थे, जो यह जानते थे कि कब कठिन निर्णय लेने का वक्त है और दूसरे पक्ष को समायोजित करते हुए कब उसे कार्यान्वित करना है।

जेटली हमारे देश के संविधान की भावना से संप्रेरित हृदय से लोकतंत्रवादी थे और उसके अधीन वहां के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के कट्टर संरक्षक थे। बहुतों को यह याद नहीं होगा कि जेटली नागरिक अधिकारों के आंदोलन में सक्रिय थे और पीयूसीएल बुलेटिन शुरू करने में मदद कर रहे थे। वे 1977 में लोकतांत्रिक युवा मोर्चा के संयोजक भी थे। आपातकाल का विरोध करने के कारण उन्हें मेरी तरह 19 महीने की जेल हुई थी।

अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों से जेटली भ्रष्टाचार के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने 1973 में जय प्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। बाद में उन्होंने जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के अभियान का समर्थन किया। इस प्रतिबद्धता ने ही जेटली को वित्तीय अनियमितताओं और अपराधों के खिलाफ संसद के कुछ विधेयकों का पुरोधा बना दिया। जेटली ने स्वयं को एक उत्कृष्ट

शेष पेज नं. 14 पर...

वैचारिक राजनीति के अग्रदूत

प्रभात झा

जो आया है, उसे तो जाना ही है। क्योंकि जब कोई जाता है तभी धरा पर कोई आता है। विश्व में अभी तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो जाने वाले का पता लगा ले कि वह कहां गया? पर यह शास्त्र साफ़ शब्दों में कहता है कि जीवन का सोलहवां संस्कार मृत्यु है। लेकिन मौत इतनी निर्दयी होगी, ऐसा पता नहीं था। पता तब लगा जब एक होनहार वीरवान को असमय हम देशवासियों के बीच से उठा ले गया। 'अरुण' तो अभी अपने अरुणोदय से देश को, अपने विचार को आलोकित ही कर रहा था कि मौत ने उसका घर देख लिया। मौत तुझे ऐसा नहीं करना था। जरूर हम लोगों से कोई गलती हुई होगी, अतः उन्हें तुम हमसे असमय छीन कर ले गए।

'अरुण जेटली' ने अपने जीवन की लकीर स्वयं खींची। उन्होंने विचारों की प्रतिबद्धता की परीक्षा सन 1975 में ही शत-प्रतिशत अंक से पास कर ली थी। इंदिरा गांधी ने सन 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया। उस दौरान अरुण जेटली सिर्फ 23 वर्ष के थे। लेकिन आजादी की दूसरी लोकतंत्र की लड़ाई के वे भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में एक सेनानी थे। उन्हें जेल की सींखचों में डाल दिया गया। वे घबराये नहीं। वे बड़े घराने के बेटे थे। लेकिन उन्होंने अपने विचारों की माथा को ऊंचा रखने के लिए इंदिराजी के सामने अपना माथा नहीं झुकाया। उलटे 19 महीने जेल में रहे। विचारों के प्रति प्रतिबद्धता का इससे बड़ा अनुपम उदाहरण और नहीं मिल सकता।

उनके लक्ष्य तय हुआ करते थे। वे मित्र में इत्र की तलाश नहीं करते थे। यही कारण है कि उन्होंने सदैव मित्रता निभाई। यही कारण है कि बहरीन की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को हज़ारों भारतीयों के बीच में पुकारा और कहा कि, "मेरा दोस्त अरुण चला गया।" आज आपको सब कुछ मिल सकता है और मिल भी जाता है, पर एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत कठिन हो गया है। राजनैतिक जीवन में तो दोस्त मिलना ही दुर्लभ है। क्योंकि यहां तो स्वार्थ का मेल-मिलाप होता है। यहां का संबंध जिनसे है, वह भी समझता है कि क्यों दे और जो संबंध रखता है वह भी समझता है कि उनसे कब तक सम्बन्ध रखना है।

पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की दोस्ती की मिसाल भारत में हर दिन और हर पल दिया जाएगा। विचारों का लगाव था। स्वार्थों की दोस्ती नहीं थी। यहीं कारण है कि श्रीमती संगीता जेटली को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया तो श्रीमती जेटली ने कहा कि, "आप अपने कर्तव्य पथ पर रहें, और कार्य पूरा करके आएं।" श्रीमती जेटली का यह सन्देश भी दर्शाता है कि अरुण जेटली ने अपने परिवार को भी विचारों और कर्तव्यपथ से जोड़कर रखा था।

अरुण जेटली बेबाक थे। वे प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। वे कुशल वक्ता थे। साथ ही ऐसे प्रवक्ता थे जिन्हे सुनने के लिए लोग टीवी पर आतुर रहते थे।

सन 2003 में दल का निर्णय हुआ कि मुझे दिल्ली आना है। मैं, प्रकाश जावडेकर और श्याम जाजू संगठन के निर्णय से दिल्ली आये। हम लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं थी। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे एक दिन अरुणजी के पास आये और कहा कि दो कार्यकर्ता महाराष्ट्र से और एक मध्य प्रदेश से हमने दिल्ली में दल के कार्य के लिए बुलाया है। उन्हें रहने की व्यवस्था करनी है। जेटलीजी ने छूटते ही कहा कि ठाकरेजी आपका आदेश! मैं तो अपने 9 नंबर अशोका रोड में रहता नहीं हूं। तीनों की व्यवस्था यहीं कर देते हैं। इसके बाद हम तीनों 9 अशोका रोड में रहने लगे।

धीरे-धीरे वह हम सभी को बुलाते रहते थे और पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं। एक दिन की घटना है। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आज तुम मेरे घर चलोगे। मैं हतप्रभ रह गया। वे अपनी गाड़ी में शाम को ले गए। उन्होंने अनेक बातें की और कहा कि मुझे एक संघ के अधिकारी ने कहा है कि तुम अपने संपर्क से पार्टी में आने वाली दूसरी पीढ़ी को आगे लाओ बल्कि उनको गढ़ने का काम करो। उन्होंने उस दिन कहा कि तुम बताओ कि सामान्य कार्यकर्ता मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैंने कहा कि सभी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। इस तरह वे जीवन के हर पहलू पर विचार करते थे। उनकी सरलता और महानता को मैंने करीब से देखा। वे कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता थे। उन्हें शौक था अपने से उन छोटों को गढ़ने का जिसमें भारत और भाजपा की समझ हो।

मैं सन 2008 में राज्यसभा में आया। रेल बजट पर बोलने का उन्होंने अवसर दिया। मैं जब बोला तो मेरी सीट पर आकर कहा कि अच्छा और तर्कयुक्त बोले। बधाई! मन गदगद सा हो गया। इतना ही नहीं, वे 'कमल संदेश' का सम्पादकीय नियमित पढ़ते थे। वे मार्गदर्शन भी देते थे। सदन के भीतर हम जैसे लोगों को उन्होंने ऊंगली पकड़कर सिखाया कि आप जब बोलते हो तो भारत देखता है और भारत भाजपा के बारे में सोचता है।

'अरुण जेटली' का दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ से बहुत लगाव था। वे कार्यकर्ताओं का अध्ययन करते थे। आज जो भाजपा की द्वितीय पंक्ति की टीम है उसे गढ़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वे संसद के दोनों सदनों के गौरव थे। उनके भाषण की जब सूचना मिलती थी तो पत्रकार दीर्घा, दर्शक दीर्घा और सदन की उपस्थिति ही नहीं होती थी, पूरा

सदन आतुर रहता था कि अब अरुणजी क्या बोलेंगे। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। उन्होंने उस दायित्व का न केवल कर्तव्यपूर्ण बल्कि देशहित में अनेक ऐसे खुलासे किये कि जो यूपीए सरकार के लिए गले की हड्डी बन गयी। वे तर्कों के साथ तथ्यों को रखते थे। देश के हर प्रांत में आने वाली पीढ़ी से उनका संपर्क रहता था। वे सदैव बोलते थे कि हम अपनी बात स्पष्टता से उचित स्थान पर रखते हैं। दल ने माना तो ठीक। नहीं तो जो दल ने निर्णय लिया, उसे पूरा करने में वे जुट जाते थे।

भाजपा या एनडीए सरकार या मोदीजी की सरकार, जब भी विपक्ष के घेरे में आयी तो उसका अरुण जेटली ने सदैव उसे अभिमन्यु की तरह विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ा। वे सेंट्रल हाल की शान थे। सेंट्रल हाल में आते ही पत्रकार उनकी ओर चुंबक की तरह खींचते चले आते थे। फिर क्या सब दिल खोलकर बात करते थे। वर्षों तक 9 अशोका रोड में पत्रकारों के सदैव प्रिय रहे अरुण जेटली। उन्हें दल में संकटमोचक कहा जाता रहा। उनके सभी दलों में मित्र थे। उनकी मित्रता विचारों से ऊपर थे। देश में हज़ारों लोग ऐसे थे, जो संघ और भाजपा के समर्थक तो थे, पर स्वयंसेवक या कार्यकर्ता नहीं थे। उन सभी को सदैव जोड़े रखने का काम अरुण जेटली करते थे। देश में एक ऐसा वर्ग जो सीधे-सीधे राजनीति में नहीं होता है, उनके बीच अरुण जेटली बहुत लोकप्रिय थे।

'अरुण जेटली' एक व्यक्ति का नाम अक्सर लेते थे। वे थे राजकुमार भाटिया। अरुणजी कहते थे कि मुझे विद्यार्थी परिषद में लाने वाले, विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ाने वाले राजकुमारजी ही थे। मैं इन्हीं के कारण परिषद से जुड़ा। वे व्यक्तियों के आकलन में कभी धोखा नहीं खाते थे। खासकर उनकी उन लोगों से बहुत नाराजगी थी, जो राजनीति में अवसरवादी होते हैं। वे ऐसे लोगों से से दल को मात्रा आगाह करते थे।

इतना ही नहीं विश्व से लेकर भारत की राजनीति और उसमें भी भाजपा सहित सभी दलों की, सभी नेताओं की उन्हें जानकारी रहती थी। हमने राजनीति में अनेक लोग देखे। उनमें से विचारों के प्रति ईमानदार और अपने जीवन में मूल्यों और नैतिकता के प्रति ईमानदार व्यक्ति का नाम अरुण जेटली था, हम गर्व से कह सकते हैं। पूरा जीवन पारदर्शिता से भरा था।

हमें अवसर मिला उनके साथ एक नहीं अनेक राज्यों में मीडिया का काम करने का। उनके न्यूज़सेंस के सभी कायल थे। अनेक पत्रकार उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। वे सबके साथ मित्रता रखते थे, पर उनका सबसे अच्छा 'दोस्त' उनकी विचारधारा थी। दिल्ली में जब उन्होंने कार्य शुरू किया और आगे बढ़ते गए तो दिल्ली का एक ऐसा वर्ग जो अपने को 'एकेडेमिक' मानता था, वह भी कहने लगा कि अब भाजपा में भी अकादमिक लोगों के आने की शुरुआत हो गयी। वे अपने कर्मों और विचारों की प्रतिबद्धता से आगे आये। वे भ्रष्टाचारी और चाटुकारों से सदैव सतर्क रहते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि ऐसे लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती, अर्थात् हम सभी को धैर्य से काम करना चाहिए।

अरुणजी हम सबको छोड़कर चले गए। वे काया से जरूर चले गए, पर उनकी विचारों की छाया में भाजपा ही नहीं, देश की आने वाली पीढ़ी सदैव पल्लिवत होती रहेगी। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य हैं)

पेज नं. ११ को शेष -

सांसद और प्रखर प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया। 2014-19 के दौरान, वह संसद के भीतर और बाहर सरकार के सबसे प्रभावी संप्रेषक थे, जिन्होंने सभी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनके पास सरकार और उनकी पार्टी की बुनियादी स्थिति और दृष्टिकोण से समझौता किए बिना समाधान प्रस्तुत करने की सहज और अद्वितीय क्षमता थी। मैंने उन्हें राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में ऐसा करते देखा है जब भी वहां कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ था।

जो बात जेटली को औरों से अलग बनाती है, वह थी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी समझ और इस पर उनकी अभिव्यक्ति। उनकी गहरी बौद्धिक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं और प्रासंगिकतापूर्ण विषय प्रस्तुति ने उन्हें एक प्रभावी आवाज की पहचान दी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुःख की बात है कि वह आवाज अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन उनकी विरासत सभी संबंधित लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी। इस साल आम चुनावों के बाद जेटली ने अपने स्वास्थ्य के कारण सरकार से बाहर होने का विकल्प चुना क्योंकि वे ऐसा कोई पद नहीं चाहते थे जिसका वह पूर्ण निर्वाह न कर सकें। यह एक दुर्लभ चारित्रिक वैशिष्ठय है।

निजी तौर पर, हम दोनों अच्छे भोजनप्रेमी थे। शुरुआती दिनों में, हम सभी लोकप्रिय रेस्तरां में जाते थे और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाते थे। सभी अवसरों पर मेरे निवास पर उनका नियमित आथित्य होता। उनका घर एकमात्र ऐसा स्थान था जहां मैं सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों पर और व्यक्तिगत रूप से जाता था। भोजन करते समय हम विभिन्न उभरते मुद्दों पर बात किया करते थे और विचारों का आदान-प्रदान करते थे। हमारी नियमित बैठकें भोजन और चिंतन, दोनों के लिए थीं।

अगस्त का यह महीना अरुण जेटली और इससे पहले सुषमा स्वराज और जयपाल रेड्डी को खोने से बहुत कम समय में बहुत अधिक तनावपूर्ण रहा है। तीनों ही योग्यतासिद्ध नेता थे और उत्कृष्ट सांसद होने के अलावा सार्वजनिक जीवन में योगदान भी देते थे।

मैं लंबे समय तह आत्मिक साथी अरुण जेटली को हमसे दूर ले जाने वाली नियति से हृदय से आहत हूं। यह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों रूप में क्षति है। उनकी आत्मा को शांति मिले। ■

(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)

(हिंदुस्तान से साभार)

मोदी सरकार के ऐतिहासिक प्रथम 100 दिन

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृढ़ संकल्प के साथ 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ लिया। निःसंदेह सरकार के प्रथम 70 दिन कई मायने में पिछली सरकारों के 70 वर्षों के कार्यों पर भारी रहा है। जिस विश्वास आकांक्षा के साथ देश की जनता ने सरकार को बहुमत दिया था उस पर मोदी सरकार शत-प्रतिशत खरी उतरी है। 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र पूर्णतः राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण को समर्पित रहा है। इसके लिये संसद ने रिकार्ड 281 घंटे काम किया, जिसमें 36 बिल लोक सभा से (जोकि 1952 के बाद सर्वाधिक), 32 विधेयक राज्य सभा द्वारा तथा 30 विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किए गए, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक हैं।

एक राष्ट्र, एक संविधान का जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब डा. अंबेडकर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और करोड़ों देशभक्तों का था वह 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के निरस्त होने के साथ पूरा हुआ। वर्षों से जम्मू और कश्मीर के साथ लेह-लद्दाख के नागरिकों की अधूरी आकाक्षांओं को पूरा करने के लिए और वहां के दलित, आदिवासी महिलाओं के साथ देश के अन्य क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वालों को समान अधिकार दिलाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम लिया गया। इस निर्णय का संसद से सड़क तक, गांव से शहर तक स्वागत और सराहना की गई।

मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और उनके सशक्तिकरण के लिए दृढ संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम संसद सत्र में सरकार के अपने 60वें दिन मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार सरंक्षण प्रदान करने के लिए, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार का सरंक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत 'तीन तलाक' प्रथा को समाप्त किया गया। इस ऐतिहासिक दिन देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को जो सदियों से तीन तलाक़ जैसी कुप्रथा से डर-डर के जी रही थी, उनको छुटकारा मिला तथा उनके जीवन में यह विधेयक नई रोशनी लेकर आया। संसद के इसी सत्र में बाल अधिकार सरंक्षण को और अधिक मज़बूत बनाने के उद्देश्य से बाल सरंक्षण (पोक्सो) (संशोधन) विधेयक, 2019 पास किया गया। इसके तहत बाल यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। पोक्सो से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई और निष्पादन के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं।

ट्रांसजैंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से लोक सभा से ट्रांसजैंडर व्यक्ति (अधिकार का सरंक्षण) विधेयक, 2019 को पास किया गया। इसमें ट्रांसजैंडर व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के रोक के साथ-साथ उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति/ ओ.बी.सी और इ.डब्ल्यू.एस. के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया। इस विधेयक के तहत विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को एक इकाई माना जाएगा, जिससे पूर्व की आरक्षण प्रणाली 200-प्वाइंट रोस्टर के आधार पर ही नियुक्तियां होंगी। ऐसे ही वेतन संहिता, 2019 अधिनियम से महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया गया एवं उनके लिए पुरूषकर्मियों के बराबर ही वेतन सुनिश्चित किया गया है। इसमें कामगारों को वेतन सुरक्षा के लिए संगठित के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के लगभग 50 करोड़ कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन का वैधानिक सरंक्षण और समय समय पर वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। वित्तिय धोखाधड़ियों पर रोक लगाने और इससे गरीबों को सरंक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने अधिनियम जमा योजना प्रतिपद्ध विधेयक 2019 को मंजूरी दी।

जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण और कल्याण को ध्यान में रखकर जनजातीय लोगों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए "गो ट्राइबल अभियान" का शुभारंभ किया गया है। ऐसे ही "जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए ई-गवर्नेंस पहल" का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में ज्यादा ई-गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण के लिए सरकार ने प्रथम 100 दिनों में देश भर में फैली वक्फ़ संपतियों का 100% डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य तय किया है। एक अन्य योजना के तहत 50% बालिकाओं सहित 5 करोड़ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 5 वर्षों में विभिन्न तरह की छात्रवृत्तियां दी जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सोशल डिफेंस, दिव्यांगजन उत्थान और सशक्तिकरण के कार्यों के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस सरकार के प्रथम 100 दिनों को ध्यान रखते हुए मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें देश का प्रथम "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान" की स्थापना, जिसको मध्यप्रदेश

के सिहोर जिले में स्थापित करने की सभी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। दूसरा प्रमुख लक्ष्य मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण रोकथाम और लोगों में बढ़ रहे सेवन के रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत देशभर में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

जल प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल वर्तमान की एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के गठन के प्रथम दिन ही एक महत्वपूर्ण कदम लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। 30 दिन के भीतर जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक विशेष जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान आज एक जन आंदोलन बन गया है। अन्नदाता किसान इस सरकार का हमेशा केंद्र बिंदु रहा है तथा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए ठोस कदम उठाए गये हैं। मोदी सरकार ने "पीएम-किसान" स्कीम के दायरे में 2 करोड़ और किसान सम्मिलित किए गये, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या अब 14.5 करोड़ हो गई है। अन्नदाताओं के सुरक्षित जीवनयापन के लिए पीएम किसान मानधन पेंशन योजना, जिसके तहत प्रथम तीन वर्षों में 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को पेंशन का लाभ मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि का निर्णय लिया गया।

सुशासन इस सरकार का मूल मंत्र है। पिछली सरकारों द्वारा हजारों ऐसे कानून बनाए गए थे जो नागरिकों, कारोबार, जीवनयापन या रोजमर्रा में बाधक थे या उनका उपयोग लोगों के परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसा अनावश्यक पुराने हो चुके लगभग 1000 से अधिक कानूनों को एक विधेयक पारित कर 2014 से अभी तक समाप्त किया जा चुका है। साथ ही न्यायिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 किया गया है। आतंकवाद से कठोरता से निपटने के लिए गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 लाया गया। सरकार अब किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी के रूप में निर्धारित करके उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। देश को लंबे समय से एक कारगर, सुरक्षित, भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन प्रणाली की आवश्यकता थी, जिसका मार्ग मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू कर प्रशस्त किया गया है। इस संशोधित अधिनियम से सड़क सुरक्षा में सुधार, परिवहन विभागों से निपटने में नागरिकों को सुविधा और ग्रामीण परिवहन, सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ स्वचालन, कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से संपर्कता में मजबूती आएगी।

सुशासन इस सरकार का मूल मंत्र है। पिछली सरकारों द्वारा हजारों ऐसे कानून बनाए गए थे जो नागरिकों, कारोबार, जीवनयापन या रोजमर्रा में बाधक थे या उनका उपयोग लोगों के परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसा अनावश्यक पुराने हो चुके लगभग 1000 से अधिक कानूनों को एक विधेयक पारित कर 2014 से अभी तक समाप्त किया जा चुका है।

पिछले 100 दिनों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गये। अवसरंचना के लिए अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश का निर्णय लिया गया है। 2019 बजट में रेलवे को देश की विकास का इंजन बनाने के उद्देश्य के तहत 2030 तक रेलवे में 50 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा और समय बचत के लिए लगभग 19,000 हजार करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नई रेल लाइने, नई ट्रेनों की सुविधा, नये रेल डिब्बे का निर्माण व ट्रेन की गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाना शामिल है। ऐसे ही ऊर्जा क्षेत्र में फास्टट्रैक विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के कार्यान्वयन के लिए कई दिशा- निर्देश जारी किये गये। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पिछले 75 दिनों में 609 करोड़ रूपये मूल्य की 88 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। 100 दिन का कार्यक्रम वन सिटी वन इम्पैक्ट आरम्भ किया गया है, जिससे 2.7 करोड लोग लाभांवित होंगे। शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 तक 23,400 करोड रूपए का निवेश और केंद्रीय सहायता से 4.26 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण कराया जाएगा।

निःसंदेह मोदी सरकार ने प्रथम 100 दिनों में देश की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक एकता और समरस्ता के लिए अनेक कार्यों के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये कार्य मोदी सरकार किसी प्रकार का कीर्तिमान स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश के 130 करोड़ों नागरिकों के प्रति अपना दायित्व समझकर कर रही थी, जिसकी पूर्व की सरकारों ने अनदेखी की थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, सभी नागरिक एक समान हैं और सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में देश की छवि व पहचान एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। भारत ने सबका साथ- सबका विकास और सबका विश्वास के अपने मंत्र को अब केवल देश तक ही सीमित ना रखते हुए पूरी दुनिया में पहुंचाया है। ■

(लेखक भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं।)

प्रधानमंत्री की फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की सफल यात्रा

'ऑर्डर ऑफ जायद' और 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां' से सम्मानित हुए नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 26 अगस्त के दौरान फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा की। उन्होंने फ्रांसीसी शहर बिआरित्ज में 25 व 26 अगस्त को जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में 'ऑर्डर ऑफ जायद' और बहरीन में 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां' से सम्मानित किया गया।

फ्रांस यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में 22 एवं 23 अगस्त को द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए और जी-7 फ्रांसीसी अध्यक्षता में बिआरित्ज में 25 व 26 अगस्त, 2019 को जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर फ्रांस की राजकीय यात्रा की।

भारत एवं फ्रांस वर्ष 1998 में रणनीतिक साझेदार बन गए और यह पारंपरिक संबंध स्थायी, भरोसेमंद, व्यापक और समान विचारधारा वाला है। भारत-फ्रांस संबंध ऐसे दो रणनीतिक साझेदारों के बीच पारस्परिक विश्वास पर आधारित है जो सदैव एक-दूसरे का साथ देते आए हैं।

दोनों पक्षों ने यह बात रेखांकित की कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होती रही है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारत-फ्रांस प्रशासनिक आर्थिक एवं व्यापार समिति (एईटीसी) द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक संचालकों के हित में बाजार पहुंच से जुड़े मसले जल्द सुलझाने के तरीके बताने के लिए एक समुचित रूपरेखा उपलब्ध कराती है।

इस संबंध में फ्रांसीसी और भारतीय कंपनियों से जुड़े व्यापार एवं निवेश के मुद्दों को सुलझाने के कार्य को संयुक्त रूप से और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। दोनों राजनेताओं ने संयुक्त रूप से इस बात पर सहमति जताई कि उच्चस्तरीय फ्रांस-भारत आर्थिक एवं वित्तीय संवाद को नए सिरे से अतिशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

डिजिटल क्षेत्र में सहयोग

दोनों देश डिजिटल क्षेत्र में उस खुले, सुरक्षित और शांतिपूर्ण साइबरस्पेस के जरिये आर्थिक एवं सामाजिक विकास को आवश्यक सहयोग देते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होता है। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों राजनेताओं ने एक साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी रोडमैप को अपनाया जिसका उद्देश्य विशेषकर उच्च प्रदर्शन युक्त कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रणनीतिक क्षेत्रों में भारत-फ्रांस द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य दोनों देशों के स्टार्ट-अप परिवेश को एक-दूसरे के करीब लाना है।

दोनों राजनेताओं ने भारत में 6 परमाणु ऊर्जा रियक्टरों के निर्माण के लिए जैतापुर, महाराष्ट्र में वर्ष 2018 में दोनों पक्षों के बीच 'औद्योगिक आगे की राह समझौता' होने के बाद एनपीसीआईएल और ईडीएफ के बीच वार्ता में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों पक्षों ने फिर से इस बात की पुष्टि की कि वे बातचीत को सक्रियतापूर्वक जारी रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं, ताकि इन्हें जल्द पूरा किया जा सके। उन्होंने 'नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र' के साथ सहयोग हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग और फ्रांसीसी वैकल्पिक ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा आयोग (सीईए) के बीच सहमति पत्र को जनवरी, 2019 में 5 साल और बढ़ाने का स्वागत किया।

भारत और फ्रांस के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग

रक्षा उद्योग में सहयोग भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी का एक मुख्य आधार है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी गणराज्य के

प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों की सूची

- भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के नेशनल एजुकेशन एंड यूथ मंत्रालय के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहयोग में प्रशासनिक प्रबंध।
- भारत के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा राष्ट्रीय संस्थान और फ्रेंच ऑल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटोमिक एनर्जी कमीशन (सीईए) के बीच समझौता ज्ञापन।
- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी वैज्ञानिक सोसाइटी प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक) और एटीओएस के बीच सहयोग का समझौता।
- संयुक्त समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए इसरो और सीएनईएस फ्रांस के बीच कार्यान्वयन प्रबंध।

राष्ट्रपति ने हस्ताक्षरित समझौतों के कार्यान्वयन, विशेषकर इसी वर्ष से प्रथम राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी करने की दिशा में हुई प्रगति पर काफी संतोष व्यक्त किया।

दोनों पक्षों ने बड़े संतोष के साथ यह बात रेखांकित की कि भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बड़ी तेजी से फ्रांस के रक्षा एवं एयरोस्पेसमूल उपकरण निर्माताओं की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दोनों पक्षों ने इस रुझान को आगे भी जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।

भारत और फ्रांस ने व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट के कार्यान्वयन के लिए गुरुग्राम के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओसीन रिजन (आईएफसी-आईओआर) में फ्रांसीसी अधिकारी की नियुक्ति का स्वागत किया।

फ्रांस और भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में प्रमुखता से सहयोग प्रदान करते है। दोनों देश अफगानिस्तान में समावेशी शांति और परस्पर विचार-विमर्श का समर्थन करते है। शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व में और अफगान के नियंत्रण में होनी चाहिए। इससे राजनीतिक समाधान स्थायी होगा।

लोगों ने नए भारत के निर्माण के लिए मजबूत जनादेश दिया है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचंड जनादेश सिर्फ एक सरकार को नहीं, बल्कि एक ऐसे 'न्यू इंडिया' के निर्माण के लिए है, जो कारोबार की सुगमता के साथ बेहतर जीवनयापन पर केन्द्रित हो।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फ्रांस में 1950 और 1960 के दशक में एयर इंडिया के दो विमान हादसों में मारे गये लोगों के सम्मान में एक स्मारक का उद्घाटन करने के बाद यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि 'न्यू इंडिया' में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बारे में स्पष्ट संकेत करते हुए उन्होंने कहा, ''भारत में अस्थायी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। आपने देखा होगा कि 1.25 अरब लोगों के देश, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण की भूमि में, उसे हटाने में 70 साल लग गए, जो अस्थायी था।"

उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के 2030 तक के ज्यादातर लक्ष्यों को अगले डेढ़ साल में ही हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2025 में क्षय रोग (टीबी) से मुक्त हो जाएगा।

जी-7 शिखर सम्मेलन, बिआरित्ज (फ्रांस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा: कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं, ट्रंप ने सहमति जताई

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर बिआरित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। श्री मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुंजाइश को 26 अगस्त को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है तथा ''हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते।"

श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। श्री ट्रंप ने श्री मोदी की इस बात का तुरंत समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर समस्या का खुद समाधान कर सकते हैं।

दोनों नेता जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर और अपनी औपचारिक बैठक से पहले रातभर चली वार्ता के बाद मीडिया के समक्ष एक साथ उपस्थित हुए।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले के बाद मोदी और ट्रंप की यह पहली मुलाकात थी।

श्री मोदी ने कहा, ''भारत और पाकिस्तान के बीच ये सभी मुद्दे द्विपक्षीय प्रकृति के हैं और हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। हम द्विपक्षीय रूप से इन मुद्दों पर चर्चा कर इनका समाधान

कर सकते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले साथ थे और उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसी अपनी समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान कर सकते हैं।

श्री मोदी ने कहा, ''चुनावों के बाद जब मैंने प्रधानमंत्री खान से बात की तो मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी इससे लड़ना है। पाकिस्तान को अशिक्षा और बीमारी से लड़ना है और भारत को भी उनसे मुकाबला करना है...मैंने उनसे कहा कि हमें अपने लोगों के कल्याण के लिये काम करना चाहिए।"

वहीं, श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और मोदी ने बीती रात कश्मीर के बारे में ''काफी विस्तार" से बात की तथा उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान खुद ही इसका समाधान कर सकते हैं।

श्री ट्रंप ने कहा, ''हमने बीती रात कश्मीर के बारे में बात की, प्रधानमंत्री को वास्तव में यह लगता है कि यह (स्थिति) उनके नियंत्रण में है। उन्होंने पाकिस्तान से बात की और मुझे विश्वास है कि वे कुछ ऐसा करेंगे जो काफी अच्छा होगा।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा, ''हम व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, हम सैन्य और कई दूसरी चीजों पर बात कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ शानदार चर्चा हुई, हम रात्रिभोज के लिये बीती रात साथ में थे और मैंने भारत के बारे में काफी जाना।"

श्री मोदी ने हाल के चुनाव में उनकी जीत पर ट्रंप द्वारा उन्हें बधाई दिए जाने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि दोनों देशों के ''साझा लोकतांत्रिक मूल्य" हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री ट्रंप की बातचीत के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक ''बेहद उत्साहवर्धक, बेहद सकारात्मक बैठक" हुई। इस साल मई में प्रधानमंत्री श्री मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद यह दोनों नेताओं के बीच तीसरी बातचीत थी।

बहरीन यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त को बहरीन का दौरा किया। भारतीय समुदाय से भी उन्होंने संवाद किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बहरीन में समकक्ष प्रिंस खलीफ बिन सलमान अल खलीफा के साथ बातचीत के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम दिए जाने की बात कही। इसके अलावा श्री मोदी ने बहरीन में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया।

भारत और बहरीन ने 24 अगस्त को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई। गौरतलब है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला बहरीन दौरा था। उन्हें प्रिंस खलीफा ने विशेष आदर देते हुए हवाई अड्डे पर रिसीव किया। ■

बहरीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसां' सम्मान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 24 अगस्त को बहरीन में 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां' से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने यह सम्मान मिलने पर कहा, 'मैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां पाकर बहुत सम्मानित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं मेरे लिए और मेरे देश के लिए आपकी मित्रता से भी उतना ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं 1.3 अरब भारतीयों की ओर से इस प्रतिष्ठित सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं।' ■

यूएई में 'ऑर्डर ऑफ जायद' से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए 24 अगस्त को उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से सम्मानित किया गया। श्री मोदी को यह सम्मान अबू धाबी में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद नाहयान द्वारा दिया गया।

सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित होकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। यह पुरस्कार भारत के सांस्कृतिक लोकाचार के लिए है और यह 130 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। इस सम्मान के लिए मैं यूएई सरकार को धन्यवाद देता हूं।' इससे पहले कई विश्व नेता इस सम्मान से सम्मानित हुए हैं, जिनमें रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और चीन के राष्ट्रपति श्री शी चिनफिंग शामिल हैं। ■

भारत-रूस के बीच हुए 15 समझौते

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस की दो दिवसीय (4-5 सितम्बर) ऐतिहासिक यात्रा की। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में श्री मोदी ने 4 सितम्बर को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच 15 अहम समझौते हुए। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। यह समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का जॉइंट वेंचर्स ऐसे कदम हैं जो हमारे रक्षा सहयोग को क्रेता-विक्रेता के सीमित परिवेश से बाहर सह-निर्माण का ठोस आधार दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तक यात्रा के दौरान हुए प्रमुख समझौते

- भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच रूसी/सोवियत सेना के उपकरणों के लिए कलपुर्जों का उत्पादन करने संबंधी समझौता।
- भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच मिलकर ऑडियो/विजुअल सह-उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने संबंधी समझौता।
- भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।
- भारत के नौवहन मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच चेन्नई बंदरगाह तथा व्लादिरवोस्तक बंदरगाह के बीच समुद्री संचार के विकास के बारे में समझौता ज्ञापन।
- रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के बारे में समझौता ज्ञापन।
- भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में योजना तैयार करना।
- रूस के सुदूर पूर्व में कोकिंग कोल खनन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सुदूर पूर्व निवेश तथा निर्यात एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।
- निवेश सहयोग के लिए निवेश भारत और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के बीच सहयोग का समझौता।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में रूस के सहयोग से बन रहे न्यूक्लियर प्लांट्स के बढ़ते स्थानीयकरण से इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सही मायनों में भागेदारी विकसित हो रही है। दूसरा, हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने ज्वेज्दा पोत निर्माण परिसर का किया दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ 4 सितंबर को ज्वेज्दा पोत निर्माण परिसर का दौरा किया और उसके प्रबंधकों एवं अन्य कर्मियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के यार्ड के दौरे के समय राष्ट्रपति श्री पुतिन भी उनके साथ थे। ज्वेज्दा यार्ड जाने से पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और हाथ मिलाया। श्री मोदी ने यार्ड के प्रबंधकों एवं कर्मियों से बातचीत की।

भारत और फार ईस्ट का रिश्ता बहुत पुराना है: नरेंद्र मोदी

5 वें पूर्वी आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फार ईस्ट का रिश्ता आज का नहीं बहुत पुराना है। भारत वो पहला देश है व्लादिवास्तोक में अपना कांसुलेट खोला। तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था। सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहां आने पर पाबंदियां थीं, व्लादिवास्तोक भारतीय नागरिकों के लिए खुला था।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि रक्षा और विकास का बहुत सा साजो-सामान व्लादिवास्तोक के जरिये भारत पहुंचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। दोनों देशों के लोगों के लिए सुख-समृद्धि का सहारा बन रहा है। भारत ने यहां एनर्जी सेक्टर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड में महत्वपूर्ण निवेश किया है। सखालिन के आयल फ़ील्ड्स भारतीय निवेश की सफलता का एक उत्तर उदाहरण है। ■

केंद्रीय गृह मंत्री ने दादरा नगर हवेली के सिलवासा में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ किया

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दादरा नगर हवेली के सिलवासा में 290 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए 1 सितंबर को कहा कि सिलवासा सुंदर पहाड़ों के बीच नदियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। कई सालों से यहां के लोग विकास की राह देख रहे थे, मगर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया गया। जिसका परिणाम है कि सिलवासा एजुकेशनल हब, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैरामेडिकल संस्थान, नई टूरिज्म पॉलिसी, सर्व सुविधा युक्त यूथ हॉस्टल, दमनदीप में 6 व दादरा नगर हवेली में 12 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, श्रमिकों को कार्य स्थल के नजदीक कम मूल्य पर पौष्टिक भोजन संबंधी श्रमयोगी प्रसाद योजना सहित अनेकों परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि संघ शासित यह राज्य संघ प्रदेश के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में द्रुत गति से विकास कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो-तीन सालों के बाद यह संघ प्रदेश व्यवस्थाओं के संदर्भ में देश में अग्रणी भूमिका में होगा।

श्री अमित शाह ने नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मोदी जी के द्वारा किए गए शिलान्यास के सारे प्रोजेक्ट आज अपनी गति पर आ चुके हैं। उनका कहना था कि इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से एमबीबीएस की शिक्षा सुदृढ़ की जा सकेगी। श्री शाह ने यह भी बताया कि आज घर-घर तक गैस और बिजली पहुंचाने का कार्य समाप्त हो चुका है। अब हर घर में नल से जल का मोदी जी का सपना साकार करना है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 2014 से 2019 के कार्य को प्रमाणित किया और श्री नरेंद्र मोदी को 2014 से ज्यादा बहुमत के साथ दूसरी बार काम करने का मौका दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पिछले 100 दिनों में बहुत सारे काम किए हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए जल जैसी एक बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत की है जो जल से संबंधित सभी विषयों को पर कार्य करेगा। श्री शाह ने कहा कि अगर पहले से शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की गई होती तो आज देश कई समस्याओं से मुक्त हो सकता था ।

केंद्रीय गृह मंत्री ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा कामाख्या से लेकर कच्छ तक पूरा देश इस फैसले पर मोदी जी के साथ खड़ा है। उनका कहना था कि पिछले 70 साल में कई सरकारें आईं, किंतु वोट बैंक की चिंता के कारण धारा 370 नहीं हटा सके।

श्री शाह ने धारा 370 तथा 35ए और यूएपीए कानून का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि देश की जनता सब देख रही है। श्री शाह ने आगे बताया कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था ठीक है और 370 हटाने के बाद एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, न ही एक व्यक्ति की मौत हुई है। उनका कहना था कि विपक्षी नेताओं के बयानों का उपयोग पाकिस्तान द्वारा विदेशों में दुष्प्रचार के लिए किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आज पार्टी

की विचारधारा से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े होने का समय है।

श्री शाह का यह भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने देशहित से संबंधित मुद्दों पर हमेशा सत्ता पार्टी का समर्थन किया है और इस देश की परंपरा है कि जब देश हित का सवाल हो तो सभी राजनीतिक दल अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ हो जाएं। उनका कहना था कि मोदी जी फैसले लेते समय वोट बढ़ेंगे या कम होंगे इस बात की चिंता नहीं करते, बल्कि मां भारती के लिए अच्छा या बुरा है इस बात का ख्याल करते हैं।

श्री अमित शाह का कहना था कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छता के लिए आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक से जंग जरूरी है। उन्होंने घर से सामान लेने जाते हुए कपड़े की थैली लेकर जाने का अनुरोध किया, ताकि प्लास्टिक मुक्त बनाकर मोदी जी के स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा सके। ■

हमारी लड़ाई आतंकियों से है और आपकी भी: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 3 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों के सरपंचों, फल उत्पादकों, व्यापारियों, आढ़तियों और फल उत्पादक एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाक़ात की। 1947 के दौरान के विस्थापितों के प्रतिनिधि मंडल ने भी केंद्रीय गृह से मुलाक़ात की।

तीनों प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह के 370 हटाने वाले साहसिक कदम के लिए बधाई दी। इस मौके पर श्री शाह ने जम्मू कश्मीर से आए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में संविधान के 73वें व 74 वें संशोधन एक्ट लागू हैं जिससे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी।

श्री अमित शाह ने सरपंचों से कहा कि आप ही अब जम्मू कश्मीर के नेता हैं और आपको व्यवस्थाओं को लोगों तक ले जाना है। उनका कहना था कि अब गांव की हुकूमत गांव के पास आ गई है। इसलिए गांव-सुधार से संबंधित सभी काम सरपंचों को करने हैं। सरपंचों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के विषय में गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी।

उनका कहना था कि भारत सरकार की 85 योजनाएं हैं और उन्हें हर गांव तक पहुंचाना है। श्री शाह ने विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा सहायता योजना, मातृत्व सहयोग योजना का उल्लेख किया। उन्होंने सरपंचों से यह भी कहा कि अब आप सब लोगों का यह दायित्व है कि इन योजनाओं के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने में गांव के लोगों की मदद करें।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बहुत शीघ्र विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती शुरू की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी सिफारिश के हर गांव से कम से कम 5 लोगों की नौकरी मिले।

मुलाकात के दौरान फल उत्पादकों ने चिंता जताई कि फसल बर्बाद न हो और उचित कीमत मिले जिसपर श्री शाह ने कहा कि संबन्धित संस्थानों से चर्चा की जा रही है ताकि छोटे से छोटे किसान से भी फसल खरीद की जा सके। इसी संदर्भ में श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू की जाने वाली सभी योजनाएं जैसे फसल बीमा योजना, किसान बीमा योजना, अब जम्मू कश्मीर के किसानों को भी उपलब्ध होगी।

श्री अमित शाह ने सभी प्रतिनिधियों से स्पष्ट रूप से कहा कि स्थितियां सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उनका कहना था कि इस विषय में किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार पर विश्वास ना करें।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी जमीन किसी से जबरन नहीं ली जाएगी तथा सरकारी जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे, अस्पताल तथा शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इन सबका का फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को ही होगा। श्री शाह ने आगे कहा कि उद्योग लगने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे तथा राज्य को विभिन्न प्रकार के टैक्सों के रूप में आय होगी जिससे वहां की जनता लाभान्वित होगी।

श्री शाह ने यह भी कहा कि अब हमें माहौल बदलना है जिससे जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को देश के साथ मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। उन्होने संभावना व्यक्त की कि बहुत जल्द ब्लॉक स्तर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

श्री अमित शाह ने प्रतिनिधियों से कहा कि हमारी लड़ाई आतंकियों और आतंकवाद से है और आपकी लड़ाई भी उन्हीं से है, इसलिए जम्मू कश्मीर में माहौल को शीघ्र से शीघ्र सामान्य बनाया जाए जिससे वहां की जनता को लाभ मिल सके।

श्री अमित शाह ने 1947 के दौरान के उन विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की जो शुरुआत में भारत के विभिन्न राज्यों में रजिस्टर हुए थे पर बाद में ये परिवार जम्मू कश्मीर में आकर बस गए। श्री शाह ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जिस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में रजिस्टर विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है उसमें ऐसे छूटे हुए विस्थापित परिवारों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। ■

एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ जन-आंदोलन का आह्वान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ दो अक्टूबर से एक ''नया जन-आंदोलन" शुरू करने का 25 अगस्त को आह्वान किया। श्री मोदी ने रेडियो पर प्रसारित अपने मासिक संबोधन 'मन की बात' में कहा कि जब देश राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती मना रहा है, तब ऐसे में ''हम प्लास्टिक के खिलाफ एक नया जन-आंदोलन आरंभ करेंगे।"

उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक कचरे के उचित संग्रह एवं भंडारण और निपटारे के प्रयासों का आह्वान किया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी अपने संबोधन में नागरिकों से अपील की थी कि वे एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें।

मन की बात में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देशभर में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान चलाते है। इस बार ये 11 सितम्बर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने-अपने घरों से बाहर निकल कर श्रमदान के ज़रिये महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। घर हो या गलियां, चौक-चौराहे हो या नालियां, स्कूल, कॉलेज से लेकर सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का महा अभियान चलाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह व ऊर्जा के साथ सवा-सौ करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया। खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया। उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तमाल को खत्म करना है। इस मुहीम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है।

उन्होंने कहा कि मेरे कई व्यापारी भाइयों-बहनों ने दुकान में एक

तख्ती लगा दी है। जिस पर यह लिखा है कि ग्राहक अपना थैला साथ ले करके ही आये। इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पायेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनायेंगे तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन-आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे में और शहर के निवासियों से अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती, एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाये।

श्री मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर विशेष दिवस के रूप में मनायें। महात्मा गांधी जयंती का दिन एक विशेष श्रमदान का उत्सव बन जाए। देश की सभी नगरपालिका, नगर-निगम, जिला-प्रशासन, ग्राम-पंचायत, सरकारी-गैरसरकारी सभी व्यवस्थाएं, सभी संगठन, एक-एक नागरिक हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं कि जब ये सारा प्लास्टिक कचरे इकठ्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आयें, डिस्पोजल की व्यवस्था हो। इसे रीसायकल किया जा सकता है। इसे ईंधन बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का भी कार्य पूरा कर सकते है। बस संकल्प चाहिए। प्रेरणा के लिए इधर-उधर देखने की जरुरत नहीं है। गांधी से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। ■

मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं कि जब ये सारा प्लास्टिक कचरे इकठ्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आयें, डिस्पोजल की व्यवस्था हो। इसे रीसायकल किया जा सकता है। इसे ईंधन बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का भी कार्य पूरा कर सकते है। बस संकल्प चाहिए। प्रेरणा के लिए इधर-उधर देखने की जरुरत नहीं है। गांधी से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है।

फ्रांस में फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बहरीन में बहरीन के शाह हमाद बिन इसा अल खलीफा से 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां' सम्मान प्राप्त करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अबू धाबी में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद नाहयान से 'ऑर्डर ऑफ जायद' सम्मान प्राप्त करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

फ्रांस के बिआरित्ज में जी–7 सम्मेलन में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

व्लादिवोस्तोक (रूस) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन

व्लादिवोस्तोक (रूस) में पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन में श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19